वर्ष : 04 अंक : 268

गाजियाबाद, बुधवार 18 फरवरी 2026

पृष्ठ-6 मूल्य : दो रूपये

RNI No - UPHIN/2022/84480

E-mail: swastiksaharanews@gmail.com

www.swastiksahara.com

बिना कुछ किए बिताने वाले जीवन की अपेक्षा गलतियाँ करते हुए बिताने वाला जीवन अधिक सम्माननीय होता है

नई दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, मेरठ, हापुड़ और एनसीआर में सर्वाधिक प्रसारित

स्वास्तिक सहारा

गाजियाबाद से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

भारत-फ्रांस की मेगा डिफेंस डील

अब भारत में बनेंगे एवरेस्ट तक उड़ने वाले हेलीकॉप्टर

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने मंगलवार को मुंबई में हुई व्यापक द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहयोग, व्यापार और स्वास्थ्य क्षेत्रों में 20 से अधिक समझौतों और परिणामों की घोषणा की। राष्ट्रपति मैक्रॉन नई दिल्ली में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेने और भारतीय नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय चर्चा करने के लिए तीन दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। वार्ता में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। मुंबई में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत-फ्रांस साझेदारी वैश्विक स्थिरता की एक ताकत है। उन्होंने फ्रांस को भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया और कहा कि राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ मिलकर दोनों देशों ने अपने संबंधों को को जन-केंद्रित सहयोग में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष की शुरूआत के साथ, हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को जन-सहयोग की साझेदारी में बदल रहे हैं। क्योंकि नवाचार अकेले नहीं, बल्कि सहयोग से ही संभव है। उन्होंने आगे कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना और रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उद्योगों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छात्रों और शोधकताओं को आपस में जोड़ना है। इसी पहल के तहत, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, हम स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के लिए भारत-फ्रांस केंद्र, डिजिटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत-फ्रांस केंद्र और विमानन कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शुरू करने जा रहे हैं। अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी भरोसे और साझा दृष्टिकोण के आधार पर, आज हम अपने संबंधों को एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष की शुरूआत की घोषणा करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बड़ी छलांग! राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में मिसाइल एकीकरण सुविधा का किया उद्घाटन

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। भारत की रक्षा क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक दिन रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) का दौरा किया, जहाँ उन्होंने न केवल अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया, बल्कि स्वदेशी तकनीक की शक्ति का भी प्रदर्शन किया।

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने आकाश तृतीय और चतुर्थ रेजिमेंट युद्ध प्रणालियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और 'माउंटेन फायर कंट्रोल रडार' का अनावरण किया। सिंह ने पुणे में स्थित कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र (सीओई-एआई) का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया और औपचारिक रूप से कंपनी की एआई नीति की शुरूआत की।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय मंत्री को भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा विकसित एआई-आधारित समाधानों सहित कई उन्नत स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी दी गई, जो रक्षा तंत्र में नवाचार और स्वदेशीकरण पर बढ़ते जोर को उजागर करता है। सिंह ने इस बात को स्वीकार किया कि हवाई क्षेत्र रक्षा और ड्रोन-विरोधी अभियानों में विकसित प्रणालियों ने यह प्रदर्शित किया है कि भारत के स्वदेशी समाधान वैश्विक मानकों को पूरा कर सकते हैं।

रक्षा मंत्री का संदेशः हवाई क्षेत्र की रक्षा और ड्रोन-विरोधी अभियानों में हमारे समाधानों ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है।

'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का उल्लेख

समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का विशेष जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे स्वदेशी रूप से विकसित वायु रक्षा और ड्रोन-रोधी प्रणालियों ने दुश्मन के खतरों को बेअसर करने में प्रभावी भूमिका निभाई। उन्होंने गर्व से कहा कि भारत की स्वदेशी प्रणालियाँ अब वैश्विक मानकों को टक्कर दे रही हैं।

युवाओं और स्टार्टअप्स से संवाद

मंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा विकसित एआई-आधारित समाधानों का अवलोकन किया। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों और उद्यमियों को प्रेरित करते हुए कहा कि रक्षा तंत्र में नवाचार और स्वदेशीकरण ही भारत को वैश्विक शक्ति बनाएगा।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया, 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिसमें कुल 53,37,778 परीक्षार्थी शामिल होंगे। नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम लखनऊ में टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001806607 और 18001806608 उपलब्ध हैं। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001805310 और 18001805312 हैं।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने मंगलवार को ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। कुल 8033 परीक्षा केंद्रों में 596 राजकीय, 3453 अशासकीय सहायता प्राप्त और 3984 स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। 18 जिलों को संवेदनशील और 222 केंद्रों को अति संवेदनशील, जबकि 683 केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है।

प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में वॉयस रिकॉर्डर युक्त 2 सीसीटीवी कैमरे, राउटर, डीवीआर और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लगाए गए हैं, जिससे वेबकास्टिंग के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। परीक्षा में 8033 केंद्र व्यवस्थापक, 8033 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, 8033 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 1210 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 427 जोनल मजिस्ट्रेट और 69 मंडलीय व 440 जनपदीय सचल दल नियुक्त किए गए हैं।

प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त रिजर्व सेट्स की व्यवस्था की गई है, जिन्हें सुरक्षित डबल लॉक अलमारी में सील बंद करके रखा जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं पर माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो और सूक्ष्म आकार में वढटरढ अंकन होगा। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम द्वारा यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद परीक्षा 2026 की भी पहली बार ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024' लागू किया गया है, जिसके तहत अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है।

बाल सुधार गृह से दो पाकिस्तानी नागरिकों समेत तीन बंदी फरार, पुलिसकर्मियों पर हमला और फायरिंग से हड़कंप

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र आर.एस. पुरा में स्थित एक बाल सुधार गृह में सोमवार शाम को सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए तीन बंदी फरार हो गए। फरार होने वालों में दो पाकिस्तानी नागरिक और एक स्थानीय गैंगस्टर शामिल है। इस घटना के दौरान बंदियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। अधिकारियों के अनुसार, घटना शाम करीब 5.15 बजे आर.एस. पुरा स्थित बाल सुधार गृह में हुई। पुलिस ने बताया कि फरार बंदियों की पहचान आर एस पुरा में डबलेहार निवासी कराजीत सिंह उर्फ गुग्गा तथा पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद सुना-उल्लाह और एहसान अनवर के रूप में हुई है। तीनों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर हमला किया और इसके बाद परिसर से भाग निकले। अधिकारियों ने बताया कि एसपीओ विनय और मुख्य आरक्षक प्रवीण नामकदो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। खौफ गिरोह से जुड़े बताए जा रहे एक गैंगस्टर का बाल सुधारगृह के अंदर कुछ गोलियां चलाते हुए एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में चिंता पैदा हो गई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि स्थानीय स्तर पर निर्मित पिस्तौल कैदी तक कैसे पहुंची। फरार बंदियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई हैं और विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। इसी बीच, पूर्व डीजीपी एस पी वैद ने घटना को लेकर पुलिस से सवाल किया और कहा कि दिलचस्प बात यह है कि तीनों कैदी अब नाबालिग नहीं हैं।

पुलिस की कार्रवाई और घेराबंदी

घटना का संज्ञान लेते हुए जम्मू पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। सीमावर्ती इलाकों और संभावित ठिकानों पर सघन छापेमारी जारी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित होने के कारण सीमा सुरक्षा बल (इरक्ष) को भी सतर्क कर दिया गया है ताकि पाकिस्तानी नागरिक सीमा पार न कर सकें।

महाशिवरात्रि पर 'कुट्टू' का आटा खाने से दर्जनों लोग बीमार

पुलिस ने गोदाम सील कर 4 को हिरासत में लिया

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नोएडा। दिल्ली से सटे नोएडा के बिसरख क्षेत्र में महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान दूषित कुट्टू का आटा खाने से कई सोसायटियों के निवासियों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इस गंभीर घटना के बाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक जनरल स्टोर और एक मसाला गोदाम को सील कर दिया है। पुलिस के अनुसार, रविवार को महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान कुट्टू के आटे से बने व्यंजन खाने के बाद सुपरटेक ईकोविलेज 3, रॉयल कोर्ट सोसाइटी और हिमालय प्राइड सोसाइटी के निवासियों ने उल्टी, दस्त और घबराहट जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायत की। सोमवार को एक निजी अस्पताल से सूचना मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। खाद्य विभाग और बिसरख पुलिस की संयुक्त टीम ने सुपरटेक ईकोविलेज 3, रॉयल कोर्ट सोसाइटी और हिमालय प्राइड सोसाइटी में स्थित दुकानों का निरीक्षण किया और दुकानों से आटे के नमूने एकत्र किए।

तारिक रहमान बने बंगलादेश के नये प्रधानमंत्री, 49 मंत्रियों ने भी ली शपथ

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के प्रमुख तारिक रहमान ने मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 49 अन्य सांसदों को मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने श्री रहमान और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। श्री रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाग लिया। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी थे। देश में 36 सालों के बाद कोई पुरुष देश का प्रधानमंत्री बना है। मंत्रिमंडल में 25 कैबिनेट मंत्री तथा 24 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, अमीर खुसरू महमूद चौधरी, सलाहुद्दीन अहमद, इकबाल हसन महमूद, मेजर (सेवानिवृत्त) हाफिज उद्दीन अहमद, अबू जफर मोहम्मद जाहिद हुसैन, डॉ. खलीलुर रहमान, अफरोजा खानम रीता और निताई रॉय चौधरी शामिल हैं।

मोहाली फोर्टिस अस्पताल में भर्ती भगवंत मान, अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। पंजाब के मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल और आसपास के स्कूलों को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। यह धमकी खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से जारी की गई है। मोहाली और चंडीगढ़ में पहले भी इसी तरह की धमकियां मिली हैं, लेकिन वे झूठी साबित हुई हैं। इसके बावजूद, पंजाब पुलिस मामले की सक्रिय रूप से जांच कर रही है। सोमवार शाम को अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ ही घंटों बाद सीएम मान को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में दोबारा भर्ती कराया गया। सूत्रों के अनुसार, थकान के कारण उन्हें अस्पताल लौटना पड़ा।

इससे पहले, मान अस्पताल से निकलकर सीधे मोगा गए थे, जहां उन्होंने नशा-विरोधी अभियान 'युद्ध नशियान विरुद्ध' के एक कार्यक्रम में भाग लिया। वहां सभा को संबोधित करने के बाद, वे आगे के इलाज के लिए अस्पताल लौट आए। अहमदाबाद के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को अहमदाबाद के स्कूलों को हाई अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि अधिकारियों को विस्फोटों की चेतावनी देने वाले धमकी भरे ईमेल मिले थे।

भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अव्यवस्था पर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मांगी माफी, बोले- भीड़ अभूतपूर्व थी

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पहले दिन हुई दिक्कतों के लिए लोगों से माफी मांगी। इस सम्मेलन को दुनिया के सबसे बड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलनों में से एक बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में लोगों की उपस्थिति अभूतपूर्व थी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार खुले विचारों वाली है और उपयोगकताओं को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए सुझावों पर विचार करने को तैयार है।

कार्यक्रम में बढ़ती दिलचस्पी के कारण अत्यधिक भीड़भाड़ को लेकर ऑनलाइन हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि आज शिखर सम्मेलन में 70,000 से अधिक लोग शामिल हुए हैं और आगंतुकों, गणमान्य व्यक्तियों और प्रदर्शकों के बीच उत्साह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन है। प्रतिक्रिया अभूतपूर्व रही। उत्साह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि अब आयोजन बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। यदि किसी को कल कोई समस्या हुई हो, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, कृपया हमारे साथ साझा करें। हम खुले विचारों वाले हैं। हम आप सभी के लिए इस अनुभव को और भी सुगम और सुखद बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास एक रणनीतिक बैठक कक्ष है जो कल से ही कार्यरत है। मेरी पूरी टीम इस शिखर सम्मेलन के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत कर रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुझे लगता है कि डीपफेक पर सख्त नियमन की जरूरत है। यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमें अपने समाज को इस नुकसान से बचाना होगा। हमने इस विषय पर उद्योग जगत के साथ बातचीत शुरू कर दी है।

वैष्णव ने कहा कि चाहे वह नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, मेटा हो या एक्स, सभी को भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हम 'एआई का यूपीआई' बनाएंगे, जो भरोसेमंद समाधानों का एक समूह होगा और इसे यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर लोग अपने प्रोजेक्ट बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक, आने वाले दो वर्षों में, हमें एआई स्टैक की पांचों परतों में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश देखने को मिलना चाहिए।

न्यूजक्लिक और उसके चीफ एडिटर पर ईडी का बड़ा ऐक्शन, 184 करोड़ का लगा जुर्माना

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक की मालिक कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड और इसके संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्था पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के कथित उल्लंघन के लिए 184 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया है। एजेंसी के अनुसार, कुल जुमार्ने में से 120 करोड़ रुपये कंपनी पर लगाए गए हैं, जबकि पुरकायस्था पर इसी आदेश के तहत 64 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया गया है। यह कार्रवाई फेमा की धारा 16 के तहत शिकायत दर्ज होने के बाद शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही के बाद की गई है। ईडी ने कहा कि निर्णायक प्राधिकरण ने दस्तावेजी साक्ष्य, वित्तीय रिकॉर्ड और पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि कंपनी और उसके निदेशक ने विदेशी मुद्रा नियमों का बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित रूप से उल्लंघन किया है। कथित उल्लंघनों में बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा लेनदेन और नियामक प्राधिकरणों को प्रस्तुत वैधानिक घोषणाओं में विसंगतियां शामिल हैं।

एजेंसी ने बताया कि न्यूजक्लिक ने आधिकारिक दस्तावेजों में अपने व्यवसाय की प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करके, क्षेत्रीय शर्तों और प्रवेश मार्ग की आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए, 2018-19 के दौरान लगभग 9.59 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया। एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि 2018-19 और 2023-24 के बीच प्राप्त 82.63 करोड़ रुपये की विदेशी आवक प्रेषण राशि को पर्याप्त दस्तावेजीकरण या अनिवार्य SOFTEX फॉर्म जमा किए बिना निर्यात आय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ईडी ने दावा किया कि इन लेन-देनों को इस तरह से संरचित किया गया था जिससे विदेशी मुद्रा विनियमों के उद्देश्यों को विफल किया जा सके।

हिन्दू सम्मेलन में सामाजिक एकता और सनातन चेतना का हुआ विराट संगम

शहीद प्यारे लाल शर्मा पार्क, मालीवाड़ा में सर्व हिन्दू समाज के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जुटे सैकड़ों लोग

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। मालीवाड़ा स्थित शहीद प्यारे लाल शर्मा पार्क में सर्व हिन्दू समाज द्वारा विराट हिन्दू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सनातन संस्कृति, सनातन धर्म एवं सामाजिक एकता के प्रतीक समाज के अनेक सम्मानित महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति रही। सम्मेलन का उद्देश्य हिन्दू समाज में जागरण, एकता एवं सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ कथा वाचन एवं भजन गायक संजय रैना के मधुर भजनों से हुआ, जिसने वातावरण को भक्तिमय और प्रेरणादायी बना दिया। इसके उपरांत राष्ट्र चेतना एवं भारतीय संस्कृति के प्रखर वक्ता सुनील कौशल ने आशीर्वचन प्रदान किए। उन्होंने अखंड भारत विषय पर अपने संबोधन में भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्र निर्माण में हिन्दू समाज की भूमिका को रेखांकित किया।

प्रेरक उद्बोधन में विद्या भारती पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड क्षेत्र के संगठन मंत्री डोमेश्वर साहू ने संघ के सौ वर्ष की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए हिन्दुत्व और भारतीय एकता की महत्ता को विस्तार से समझाया। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि सभी जाति-पाति से ऊपर उठकर एकजुट हों और सनातन मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र को सशक्त बनाएं। उनका कहना था कि हिन्दू समाज की एकता ही देश की मजबूती का आधार है।

इसके पश्चात संघ के गाजियाबाद विभाग प्रचारक अतुल ने संघ की कार्यशैली के अनुरूप पंच परिवर्तन विषय पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने परंपरा, संस्कृति और धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक समरसता और एकता को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। इससे पूर्व बालक सक्षम चौहान ने प्रभावशाली कविता पाठ प्रस्तुत किया, जिसमें शिवाजी और पायलट अभिनंदन को समर्पित पंक्तियां शामिल रहीं।

मालीवाड़ा स्थित शहीद प्यारे लाल शर्मा पार्क में आयोजित विराट हिन्दू सम्मेलन को सफल बनाने में हिन्दू सम्मेलन आयोजन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समिति के अध्यक्ष गोपीचन्द, संरक्षक शेर सिंह के मार्गदर्शन में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और सभी पदाधिकारियों व सदस्यों के सहयोग से आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया गया।

आयोजन समिति में सचिव सूरज सैनी और बी डी आर्या ने कार्यक्रम संचालन एवं व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी निभाई। उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने समन्वय और संपर्क का कार्य संभाला। समिति में विकम सैनी, जतन कौर, अमित तितौरिया, मुकेश सैनी, विकास कुमार गौतम, रामवती, दिलीप सैनी, अमित गौतम और सिद्धार्थ गौतम ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया।

सहसचिव रविन्द्र शर्मा ने व्यवस्थाओं की निगरानी करते हुए आयोजन को सुचारु रूप से आगे बढ़ाया। कोषाध्यक्ष प्रशाक गुप्ता ने आर्थिक प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाई। समिति के सदस्यों में ला. महेन्द्र, जगदीश, महेन्दु, दिनेश मुनीम, मंगू, सतेन्द्र, अशोक, पप्पू, पूजा अग्रवाल, मनोज जिन्दल, अनिल, हरिओम वर्मा, सरला, देवेन्द्री, द्रोपदी, पुष्पा, बाला और सरस्वती ने विभिन्न व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान किया।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक सम्पन्न

मार्केटिंग एवं पैकेजिंग एवं बिक्री के स्तर पर सतर्क, सावधान एवं सचेत रहें: अपर जिलाधिकारी

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ के निर्देशन पर अपर जिलाधिकारी (नगर) , विकास कश्यप की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, गाजियाबाद की जिला स्तरीय कमेटी बैठक महात्मा गाँधी, कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के निमित खाद्य पदार्थो विशेष कर खोया, पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पाद तथा नमकीन, पापड़, मैदा पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के निर्देश दिये गये। साथ ही विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर खाद्य लाइसेन्स / पंजीकरण के वृद्धि के निर्देश दिये गये, जिन खाद्य कारोबारकताओं के वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख रुपए से अधिक हो उनका पंजीकरण से लाइसेन्स में परिवर्तन के निर्देश दिये गये।

व्यापार मण्डल मोदीनगर के सदस्यों द्वारा मोदीनगर कस्बे में लाइसेन्स एवं पंजीकरण कैम्प लगाने हेतु आग्रह किया गया जिसपर अपर जिलाधिकारी (नगर) , गाजियाबाद द्वारा होली पर्व के पश्चात कैम्प लगाने हेतु निर्देशित किया गया। अपर जिलाधिकारी (नगर) द्वारा आर.सी की वसूली के लिए सम्बन्धित तहसील के तहसीलदारों से समन्वय स्थापित कर वसूली के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये।

अपर जिलाधिकारी (नगर) द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा आने वाले दिनों में एक चुनौती है जिसे मार्केटिंग एवं पैकेजिंग एवं बिक्री के स्तर पर सतर्क, सावधान एवं सचेत रहते हुए सुनिश्चित किया जा सकता है।

किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं को मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने के लिए मजबूर न होना पड़े, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएं। अपर जिलाधिकारी (नगर) द्वारा औषधि विक्रय के थोक एवं फुटकर दुकानों तथा ब्लड बैंकों के नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने हेतु औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया। बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड-द्वितीय, औषधि निरीक्षक एवं समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि सुशील अरोडा, संदीप बंसल, प्रवीन मित्तल, सतीश अग्रवाल एवं गौरव गुप्ता इत्यादि मौजूद रहे। बैठक में खाद्य से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के साथ-साथ उपभोक्ता प्रतिनिधि, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मण्डल, गाजियाबाद, प्रतिनिधि औषधि विक्रेता संघ गाजियाबाद उपस्थित रहे।

जनता दर्शन में जिलाधिकारी ने सुनी जन शिकायतें, अधिकारियों को दिए समाधान कराने के निर्देश

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान जनसुनवाई की गयी। जन सुनवाई के दौरान राजस्व विभाग, जीडीए, नगर निगम, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों से सम्बंधित प्रार्थना/शिकायती पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को शासन के मंशा अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने तथा जमीन से संबंधित समस्या को पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण ससमय सुनिश्चित कराएं जाने के निर्देश दिया गया। जनता दर्शन में निरंतर प्राप्त होने वाली शिकायतें, समस्याओं और निवेदनों दिव्यांगजन कल्याण विभाग,

शस्त्र लाईसेंस (विरासत), नियोजन विभाग (फैमिली आईडी), यू0पी0नेडा, पीएम सूर्य घर योजना, अवैध कब्जा/भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान आदि के निस्तारण एवं निवारण के क्रम में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देशित दिए गये। जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त सभी कार्य युद्ध स्तर पर किये जाएं, उक्त से सम्बंधित किसी भी व्यक्ति को असुविधा का सामना ना करना पड़ें। ऐसा कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जायेगा जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएं। जनता का उत्पीड़न किसी भी रूप में क्षमा योग्य नहीं हैं। जनसुनवाई के दौरान एडीएम ई ज्योति मौर्य, एडीएम जे श्रीमती अंजुम बी, एडीएम एल/ए अवनीश, एडीएम सिटी विकास कश्यप सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

संभव में प्राप्त पांच संदर्भों पर नगर आयुक्त ने अधिकारियों को दिए कार्यवाही के निर्देश

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर आयुक्त द्वारा संभव जनसुनवाई में जन समस्याओं को सुन मौके पर टीम भेज कर निस्तारण की कार्यवाही कराई गई, संभव के अंतर्गत पांच संदर्भ प्राप्त हुए जिसमें निर्माण विभाग से दो संदर्भ, प्रकाश विभाग से दो संदर्भ, तथा स्वास्थ्य विभाग से एक संदर्भ प्राप्त हुआ, राजेंद्र नगर, हिंडन विहार, संजय नगर तथा बिहारीपुर विजयनगर के निवासियों ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर नगर आयुक्त तथा निगम अधिकारियों से मुलाकात करते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। संभव के दौरान अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव, प्रभारी संपत्ति पल्लवी सिंह, महाप्रबंधक जल कामाख्या प्रसाद आनंद, प्रभारी प्रकाश आश कुमार उपस्थित रहे जिनके द्वारा प्राप्त समस्याओं के निस्तारण के लिए मौके पर टीम भेजकर कार्यवाही कराई गई।

22 फरवरी को होगा मेगा/वृहद विधिक सेवा व जागरूकता अभियान कैम्प का आयोजन

अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाएं: न्यायाधीश नीरज गौतम

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। 22 फरवरी को होने वाले मेगा/वृहद विधिक सेवा व जागरूकता अभियान कैम्प के आयोजन के उपलक्ष में जनपद न्यायालय गाजियाबाद के सभागार में एक बैठक आहूत हुई, जिसमें अध्यक्ष/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट नीरज गौतम, सदस्य/ अपर जिला जज कोर्ट संख्या -2 गौरव शर्मा व सदस्य/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय सिंह -द्वितीय, एडीएम सिटी विकास कश्यप, आईएएस अयान जैन रहे।

बैठक में कैम्प की रूपरेखा, व्यवस्थाओं एवं जनसहभागिता बढ़ाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन, विशेषकर गरीब, कमजोर एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है। शिविर का उद्देश्य आमजन, विशेषकर गरीब, कमजोर एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है।

शिविर में नागरिकों को निःशुल्क विधिक परामर्श, लोक अदालत के माध्यम से विवाद निस्तारण की जानकारी, आवेदन/प्रार्थना पत्र लेखन में सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना संबंधी मार्गदर्शन तथा महिला, बालक, वरिष्ठ नागरिक एवं श्रमिकों से संबंधित कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे तथा जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु आवेदन स्वीकार करेंगे।

आमजन से अपील की जाती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह शिविर समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों तक न्याय एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।

बैठक में परियोजना निदेशक, पुलिस विभाग, नगर निकाय यूपीएसआरटीसी, यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट, डूडा, शिक्षा विभाग, सूचना विभाग, एडीएम, स्वास्थ्य विभाग, प्लांट प्रोटेक्शन विभाग, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी, पिछड़ा कल्याण, दिव्यांग कल्याण, पंचायती राज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आरटीई में 6000 से अधिक सीटों की कटौती पर आईपीए ने उठाए सवाल

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन ने शिक्षा सत्र 2026-27 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए सीटों में 6000 से अधिक की भारी कटौती पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए जिलाधिकारी गाजियाबाद को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के अनुसार, शिक्षा सत्र 2025-26 में जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कुल 1206 विद्यालयों में 19,666 सीटें आरटीई के तहत उपलब्ध थीं। जबकि शिक्षा सत्र 2026-27 में विद्यालयों की संख्या बढ़कर 1395 हो गई है (189 विद्यालयों की वृद्धि), इसके बावजूद सीटों की संख्या घटाकर मात्र 13,527 कर दी गई है। यानी 6139 सीटों की कमी कर दी गई, जो अत्यंत चिंताजनक है। आईपीए ने इसे विद्यालयों में सीट मैपिंग की पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह बताते हुए कहा कि जब विद्यालयों की संख्या बढ़ी है, तो सीटों में कमी तर्कसंगत नहीं है। यह स्थिति हजारों आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को प्रभावित करेगी। एसोसिएशन ने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मांग की है कि आरटीई सीटों में हुई कमी की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। विद्यालयों में सीट मैपिंग की पुनः समीक्षा कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। अधिकतम पात्र बच्चों को प्रवेश दिलाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। आईपीए ने चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर विषय पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन अभिभावकों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आगे की रणनीति तय करेगा। इस मौके पर विनय कक्कड़, अमित राय, बबलू ठाकुर, अमित चौहान, राहुल शर्मा, विवेक त्यागी, सोनू शर्मा आदि मौजूद रहे।

146 ईडब्ल्यूएस भवनों का लॉटरी ड्रॉ सम्पन्न

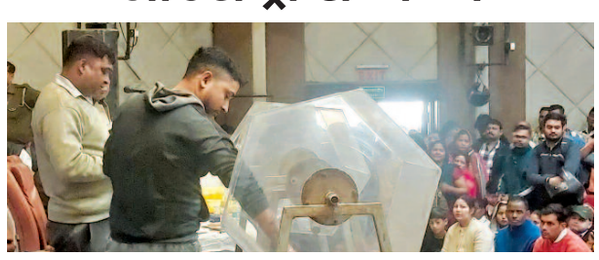

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हिन्दी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत योजना संख्या-930-41डी, निजी विकासकर्ता मैसर्स रॉकफोर्ट डवलपर्स प्रा०लि० बिल्डर्स, खसरा संख्या-1174, ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद में निर्मित 146 ई0डब्ल्यू0एस0 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) भवनों के आवंटन हेतु लॉटरी ड्रॉ का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में 13 वेटिंग सूची के आवेदकों के लिए भी लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई। संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शासन के दिशा-निदेर्शों के अनुरूप सम्पन्न की गई, जिससे सभी पात्र आवेदकों को समान अवसर सुनिश्चित हो सके।

लॉटरी ड्रॉ की कार्यवाही अपर जिलाधिकारी , गाजियाबाद, अपर सचिव , वित्त नियंत्रक , परियोजना अधिकारी तथा सी0एल0टी0सी, गाजियाबाद की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आवेदकगण भी उपस्थित रहे और उन्होंने पूरी प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा।

प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। इसी क्रम में निजी विकासकर्ता द्वारा निर्मित इन भवनों का आवंटन कर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ही आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार पारदर्शी एवं जनहितकारी आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से आमजन को आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रचार वाहन को किया हरी झण्डी दिखाकर जन जागरूकता हेतु रवाना

- प्रचार वाहन विधिक जागरूकता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा: श्री विनोद सिंह रावत

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन तक न्याय की पहुँच को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में अत्याधुनिक प्रचार वाहनों की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में आज जनपद में नव प्राप्त प्रचार वाहन का विधिवत पूजन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विनोद सिंह रावत द्वारा किया गया तदोपरांत हरी झण्डी दिखाकर प्रचार वाहन को जन जागरूकता अभियान के लिए रवाना किया गया।

कार्यक्रम के दौरान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विनोद सिंह रावत, एडीजे प्रथम श्री निरंजन चन्द पाण्डेय व श्री संजय सिंह द्वितीय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद ने अपने सम्बोधन में कहा कि यह प्रचार वाहन विधिक जागरूकता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

इसके माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता, पीड़ित प्रतिकर योजना, महिला एवं बाल संरक्षण, वरिष्ठ नागरिक अधिकार तथा अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव और घर-घर तक पहुँचाई जाएगी।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा यह भी कहा गया कि अब दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों, कमजोर एवं वंचित वर्गों, श्रमिकों, महिलाओं तथा जरूरतमन्द व्यक्तियों तक विधिक सेवाओं का सन्देश और अधिक प्रभावी रूप से पहुँचेगा।

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विनोद सिंह रावत द्वारा यह भी कहा कि इन नवीन वाहनों के संचालन से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों में गति आयेगी और पात्र लाभार्थियों का समयबद्ध पंजीकरण एवं लाभ प्रदान करना और अधिक सुगम हो सकेगा। यह पहल न्याय को केवल न्यायालय की चारदीवारी तक सीमित न रखकर समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

भारतीय किसान यूनियन (अनाज) ने मीरपुर में किसानों एवं ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज की घटना के बाद धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन किया

दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए, सभी भाकियू मिलकर आंदोलन करेंगे

स्वास्तिक सहारा संवाददाता

गाजियाबाद। लोनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मीरपुर में किसानों एवं ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज की घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन (अनाज) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. सचिन शर्मा आज किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित किसानों को अपना पूर्ण समर्थन दिया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. सचिन शर्मा ने कहा कि किसानों की न्याय की यह लड़ाई लोनी से लखनऊ तक लड़ी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि घटना में शामिल दोषी लोगों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। संवाद से समाधान निकलता है, जबकि हिंसात्मक कार्यवाही घोर निंदनीय है। उन्होंने बताया कि इस गंभीर विषय पर अन्य किसान व सामाजिक संगठनों से निरंतर बातचीत की जा रही है तथा शीघ्र ही एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पं. सचिन

शर्मा ने कहा कि शहरों में पहले ही सांस लेने की जगह नहीं बची है और अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रदूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। उपजाऊ कृषि भूमि को अनुपजाऊ बनाने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र पहले से ही ट्रोनिका सिटी के ई-कचरे और प्रदूषण से त्रस्त है। इस मौके पर (प्रदेश अध्यक्ष) निशांत भड़ाना ने कहा भारतीय किसान यूनियन (अनाज) की स्पष्ट मांग है कि गाजियाबाद नगर निगम अथवा अन्य संबंधित संस्थाएं अपने कचरे का निस्तारण दिल्ली की तर्ज पर वैज्ञानिक ढंग से कूड़ाघरों/प्लांटों में करें, तथा ऐसे प्लांट आबादी और खेती योग्य भूमि से बाहर स्थापित कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें भारतीय किसान यूनियन (अनाज) किसानों, ग्रामीणों और पर्यावरण की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी। इस मौके पर उपस्थित रहे प्रदेश अध्यक्ष निशांत भड़ाना युवा पश्चिमी अध्यक्ष सनी सेन जिला अध्यक्ष मेरठ दीपक भड़ाना युवा जिला अध्यक्ष बागपत कपिल गुर्जर प्रदेश सचिव रामगोपाल जी संजीत खारी योगी बैसला विवेक चौहान कपिल चौधरी मुकेश ठाकुर सुंदर गुर्जर धर्म सिंह नगर अभय जाटव मोहित त्यागी कमल त्यागी धर्मपाल त्यागी आदि उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड व कर-करेत्तर राजस्व की समीक्षा बैठक आयोजित

खराब रैंक लाने वाले अधिकारियों लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूरा करने तक वेतन रोकने के आदेश: जिलाधिकारी

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मॉदड़ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड जिला अनुश्रवण पुस्तिका (राजस्व से सम्बंधित) की जनवरी माह की मासिक प्रगति रिपोर्ट व कर-करेत्तर राजस्व विभाग से सम्बंधित समीक्षा बैठक आहूत हुई। बैठक में सम्बंधित विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी द्वारा उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने की चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये गये।

जिलाधिकारी ने खराब रैंक (सी व डी) लाने वाले विभागों से स्पष्टीकरण मांगा व दिये गये लक्ष्यों के सापेक्ष कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होने कहा कि लक्ष्यों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने तक सम्बंधित विभागों के वेतन रोकने हेतु निर्देश दियें। जिसमें अवस्थापना व औद्योगिक विकास, आबकारी, आवास, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, खाद्यय एवं औषधि प्रशासन, खाद्यय एवं रसद, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन, परिवहन, राजस्व, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, लोक शिकायत, वित्त विभागों के सम्बंधित जवाबदेही अधिकारी।

कर–करेत्तर की बैठक के दौरान

- अपने दायित्वों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभायें, कार्य में शिथिलता बरतने पर होगी कार्यवाही : जिलाधिकारी

जिलाधिकारी द्वारा समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि स्टाम्प देय के मांगपत्रों की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाया जाये। राजस्व, वाणिज्य कर, वाहन कर, मनोरंजन विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, व्यापार कर, खनन विभाग, सिंचाई विभाग, मण्डी सहित अन्य विभागों की वसूली कम होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने तीनों तहसीलों में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पेशगार सभी को निर्देशित किया कि वे अपने कोर्ट में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जब तक लक्ष्य के सापेक्ष लम्बित प्रकरण समाप्त नहीं हो जाते हैं, उक्त किसी को भी अवकाश नहीं दिया जायेगा। अपने दायित्वों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभायें, कार्य में शिथिलता बरतने पर कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में अपर नगर आयुक्त श्री जंग बहादुर, एडीएम ई ज्योति मौर्य, एडीएम जे श्रीमती अंजुम बी, एडीएम एल/ए श्री अवनीश, एडीएम सिटी श्री विकास कश्यप सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

ग्राम पंचायत विकास योजना पर एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। जनपद में ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से के सभागार में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, सचिव एवं पंचायत सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद प्रशिक्षक रोहित कुमार त्रिपाठी, संदीप कश्यप एवं अंजली पांडेय ने प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत विकास योजना की रूपरेखा, कार्यप्रणाली तथा विकास के प्रमुख लक्ष्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वरिष्ठ फैकल्टी हेड राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान समय में ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रभावी कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों की नौ थीमों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी और ग्राम स्तर पर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा। सहायक फैकल्टी हेड राहुल पांडेय ने अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंच सके। कार्यक्रम में प्रतिभागियों के लिए नाश्ता एवं भोजन की समुचित व्यवस्था द्वारा की गई। इस अवसर पर एजेंसी के संचालक सादिक अंसारी सहित गुलशन, विवेक मिश्रा, सूर्यकांत, विकास एवं सैकड़ों प्रतिभागी मौजूद रहे।

पावर एंजेल व नेतृत्व क्षमता कार्यशाला का शुभारंभ, 86 सुगमकताओं ने लिया भाग

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

मुरादनगर। खंड शिक्षा अधिकारी,मुरादनगर जमुना प्रसाद जी की अध्यक्षता में स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत पावर एंजेल एवं नेतृत्व क्षमता हेतु सुगमकरता की दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ डायट परिसर,असालतनगर, मुरादनगर में किया गया, जिसमें ब्लाक भोजपुर एवं मुरादनगर की 86 सुगमकताओं ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला की शुरूआत खंड शिक्षा अधिकारी श्री जमुना प्रसाद जी एवं जिला नोडल बालिका शिक्षा श्रीमती पूनम शर्मा जी द्वारा माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। ब्लॉक जेंडर नोडल एवं संदर्भदाता श्रीमती रेनू चौधरी ने सभी के परिचय के साथ रोचक गतिविधि कराई।

ब्लॉक जेंडर नोडल एवं संदर्भदाता श्रीमती अनुराधा चौधरी ने मीना मंच के गठन एवं कार्यवाही के विषय में चर्चा की। प्रतिभागियों से टूल 10 के विषय में चर्चा करते हुए आधा फुल कॉमिक पर रोल प्ले भी किया। सभी से अरमान मॉड्यूल, प्रगति के पंख, टूल 10 पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला नोडल पूनम शर्मा द्वारा ऊजार्वान संबोधन में कहा गया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पावर एंजेल एवं प्रत्येक बालिका को सशक्त करना है जेंडर इक्विटी एवं चुप्पी तोड़ो जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। प्रशिक्षण के दोनों दिन जिला नोडल पूनम शर्मा मौजूद रही।

भारत विकास परिषद नोएडा शाखा द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। भारत विकास परिषद नोएडा महानगर शाखा के द्वारा नोएडा डायबिटिक फोरम के सहयोग से सेक्टर 25 के कम्युनिटी सेंटर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 250 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं का निराकरण किया। शिविर सचिव संतोष गुप्ता ने बताया कि नोएडा में हर महीने के तीसरे रविवार को शिविर का आयोजन किया जाता है। डॉ विनोद(फिजिशियन), डॉ अमोल (सर्जन), डॉ एस पी यादव (डेंटल), डॉ ए एन कौशिक (फिजिशियन), डॉ एच एस दानू (मेडिसिन), डॉ राज चंद्र वंशी (फिजिशियन) आदि जाने माने डॉक्टर ने शिविर में अपना योगदान दिया। कैम्प संयोजक संजय गुप्ता ने बताया कि इस कैम्प में हड्डी, लिवर , खून , हृदय, थाइरोइड, फेफड़े और आंखों की जांच सफलता पूर्वक की गई। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय गतिविधि सदस्य-सम्पर्क एवं शाखा के संरक्षक राजीव अजमानी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। शाखा अध्यक्ष महेंद्र शर्मा महासचिव, उमेश कुमार सिंह और कोषाध्यक्ष नीरज गुप्ता व अन्य सदस्यों ने सभी का धन्यवाद किया।

कर्नल प्रदीप खरे ने की सांसद महेश शर्मा से मुलाकात, भेंट की स्वलिखित पुस्तक

नोएडा(स्वास्तिक सहारा)। सेक्टर 61 के निवासी कर्नल प्रदीप खरे ने सांसद डॉ महेश शर्मा से की भेंट की और अपनी पुस्तक जियो दिल से उपहार में दी। कर्नल प्रदीप खरे ने सांसद डॉ महेश शर्मा से नोएडा के 50वां स्थापना दिवस आयोजित करने के विषय में रचनात्मक सुझाव दिए। जिसमें गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले नागरिकों एवं संस्थाओं को 50 अवार्ड देने का प्रस्ताव रखा। नोएडा के पिछले 50 वर्षों में जो प्रगति हुई है उसे पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर दिखाई जाए।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी यातायात डॉक्टर चारू द्विवेदी सहायक नोडल मिशन शक्ति 05 के नेतृत्व में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति टीमों द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित कर किया गया जागरूक मिशन शक्ति टीमों ने विद्यालयों, महाविद्यालयों, बाजारों और ग्राम सभाओं में जाकर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी।

गुड टच-बैड टच, आत्मरक्षा, महिला उत्पीड़न से संबंधित विधिक प्रावधानों, हेल्पलाइन सेवाओं और साइबर अपराधों के बारे में बताया गया। ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल/लिंक, सोशल मीडिया दुरुपयोग, बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्कता बरतने की अपील की गई। किसी भी प्रकार की समस्या पर 112, 1090, 1091, 181, 1930, 1076 पर संपर्क करने की जानकारी दी गई।

देश में खेल क्रांति की ओर एक और कदम, एक हफ्ते में शालिनी सिंह ने पहलवानों की मांगों को किया पूरा

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। कुछ दिन पूर्व प्रो रेसलिंग लीग में एकजुट होकर पहुंचे नोएडा के पहलवानों को धन्यवाद देने के दौरान पहलवानों द्वारा रखी गई मांगों को शालिनी सिंह ने मात्र एक सप्ताह के भीतर पूरा कर उदाहरण प्रस्तुत किया है। पहलवानों ने बेहलोलपुर अखाड़े में मैट लगवाने तथा सरफाबाद अखाड़े में मैट कवर जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। शालिनी सिंह ने त्वरित पहल करते हुए दोनों स्थानों पर इन कमियों को दूर कराया जिसके लिए दोनों ही गांवों में ग्रामीणों द्वारा बेहलोलपुर में जयवीर पहलवान और सरफाबाद में सुबोध पहलवान के नेतृत्व में शालिनी सिंह और कुश्ती संघ नोएडा के अध्यक्ष सतपाल यादव का जोरदार स्वागत किया गया।

इस अवसर पर शालिनी सिंह ने कहा कि यह पहल केवल शुरूआत है और आने वाले समय में नोएडा को खेलों का प्रमुख हब बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। नोएडा के पहलवानों का उत्साह और समर्पण मेरे लिए प्रेरणा है।

भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष एवं सरफाबाद अखाड़े के संरक्षक सुखबीर खलीफा तथा बेहलोलपुर अखाड़े के संरक्षक कालू खलीफा ने शालिनी सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के हित में इतनी त्वरित कार्रवाई प्रेरणादायक है।सुखबीर पहलवान ने कहा कि जिस शालीनता और समर्पण के साथ शालिनी सिंह नोएडा में खेल क्रांति के लिए कार्य कर रही हैं, ऐसी नारियों को हमेशा सम्मान और पूजनीय स्थान दिया जाता रहा है और आगे भी दिया जाता रहेगा। इस अवसर पर ओमवीर यादव, लोकपाल पहलवान, जगदीश पहलवान, महेंद्र पहलवान, राजवीर पहलवान, सलेख यादव, सत्तम पहलवान, मुले पहलवान, सतपाल पहलवान एवं मोहित सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

झुका हाईटेंशन खंभा बना खतरा, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज धर्मशाला-घोरावल मार्ग पर बरैला महादेव मंदिर के पास मुख्य सड़क किनारे लगा हाईटेंशन बिजली का खंभा गंभीर खतरे का कारण बन गया है। खंभा काफी हद तक झुक चुका है और किसी भी समय गिर सकता है, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार यह खंभा वर्षों पहले हाईटेंशन लाइन के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन समय के साथ इसकी स्थिति जर्जर हो गई है। कई बार संबंधित बिजली विभाग से शिकायत किए जाने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया गया और केवल अस्थायी सहारा देकर औपचारिकता पूरी कर दी गई। यह मार्ग धर्मशाला से घोरावल को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है, जहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में राहगीर, श्रद्धालु और वाहन चालक गुजरते हैं। सड़क किनारे झुका हुआ खंभा किसी भी समय गिरकर जान-माल का बड़ा नुकसान कर सकता है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि खंभे की हालत दिन-ब-दिन और खराब होती जा रही है और हर पल दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो किसी भी समय बड़ी अनहोनी हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए खंभे को तत्काल बदला जाए या सुरक्षित रूप से दुरुस्त किया जाए, ताकि संभावित हादसे को टाला जा सके और मार्ग से गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

राहगीर/स्कूली बच्चे सहित अन्य लोग

पुलिस लाइन में महानिरीक्षक ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

सोनभद्र। पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर आर. पी. सिंह के आगमन पर पुलिस लाइन चुर्क में सलामी गार्द द्वारा उन्हें सलामी दी गई, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने गार्द का अभिवादन किया। इसके बाद प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में आगामी होली और रमजान, बोर्ड परीक्षा, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, बजट व्यय, यक्ष एप के प्रभावी उपयोग और साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा सहित सभी क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, एलआईयू और शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।बैठक में होली और रमजान के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर विशेष सतर्कता बरतने, शांति समिति बैठकों के माध्यम से पुलिस-जन संवाद मजबूत करने, सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने तथा फुट पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई, स्ट्रांग रूम की निगरानी और नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। यक्ष एप के प्रभावी उपयोग के तहत हिस्ट्रीशीटर और गैंगों का विवरण अपलोड करने तथा नेटवर्क विहीन स्थानों पर जियो टैगिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।साइबर अपराध नियंत्रण के लिए साइबर हेल्प डेस्क को सक्रिय रखने, ऑनलाइन ठगी मामलों में त्वरित कार्रवाई कर धनराशि को तत्काल लीन कराने और जनजागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया गया। साथ ही लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, महिला सुरक्षा, मादक पदार्थ तस्करी और संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बजट व्यय की पारदर्शिता, लंबित निर्माण कार्यों की समीक्षा तथा डायल 112 और कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखकर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

स्वास्तिक सहारा परिवार नें दीदी की रसोई ट्रस्ट की संचालिका रितु सिन्हा को जन्मदिन पर दी बधाई

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। स्वास्तिक सहारा परिवार की तरफ से दीदी की रसोई ट्रस्ट की संचालिका रितु सिन्हा को जन्मदिन पर बधाई प्रेषित की गई। बता दे की स्वास्तिक सहारा परिवार की तरफ से सीनियर ब्यूरो प्रफुल्ल पांडेय नें दीदी की रसोई ट्रस्ट की संचालिका रितु सिन्हा से उनके आवास पर भेंट कर उनको जन्मदिन की शुभकामना दी।

उन्होंने शुभकामना प्रेषित करते हुए कहा कि दीदी की रसोई ट्रस्ट की संस्थापिका अध्यक्ष प्रिय बहन रितु सिन्हा एक बेबाक, मेहनती और जमीन से जुड़ी, समाज सेवा में अग्रणी महिला है। उनकी साफगोई ही उनकी पहचान है और उनकी कर्मठता ही उनकी ताकत। दीदी की रसोई टेस्ट की संचालिका रितु सिन्हा ने स्वास्तिक सहारा परिवार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा की स्वास्तिक सहारा अपनी निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए जाना जाता है।

समाज उन्नति एवं समाज सेवा की खबरों को प्रमुखता से छपता है, जिससे हमें और दूसरों को भी उन खबरों को पढ़कर समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है।

आदर्श नगर पंचायत में दुर्गंध देती नहर,कचरे का अंबार

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

राहगीर/स्कूली बच्चे सहित अन्य लोग

सोनभद्र। आदर्श नगर पंचायत में सुमार दुद्धी नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर पांच के डीआर पैलेस / सिनेमा के बगल जीआईसी खेल मैदान जाने वाली मार्ग के किनारे नहर में कचरो का अंबार है। सड़ी-गली कचरों से बजबजाती नालीनुमा बंधी विभाग के नहर से निकलने वाली दुर्गंध से परेशान है और नाक बंद कर पार होने को विवश है। नगर पंचायत के सफाई व्यवस्थाओं की पोल खोलती यह दृश्य कई सवाल खड़े करते है। सफाई व्यवस्था के लिए नगर पंचायत द्वारा ब्रांड एंबेसडर की भी न्युक्ति की गई है लेकिन जिम्मेदारियों से कम और दिखावे पर ही ज्यादा भरोसा है। बताया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा नगर के चहुमुखी विकास के लिए कई निर्माण कार्य कराए जा रहे है लेकिन सफाई व्यवस्था के प्रति उदासीन है। कस्बे में कई स्थानों पर कूड़े कचरे की ढेर से वार्डवासी परेशान रहते है।जबकि नगर पंचायत द्वारा प्रति माह सफाई के नाम पर करीब लाखों रुपए से अधिक खर्च करती है। नहरों में पड़े कचरों को जरूर फ्लैक्स बोर्ड लगा कर ढकने का प्रयास किया गया लेकिन दुर्गंध को काबू करने में विफल है।

एमपीएल सीजन 5 मे महर्षि यूनिवर्सिटी ने जीत दर्ज कर फाइनल में बनाई जगह

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एमयूआईटी) द्वारा आयोजित महर्षि प्रीमियर लीग (एमपीएल) सीजन 5 अब अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल मुकाबलों में खेले गए पहले मैच में महर्षि यूनिवर्सिटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी को 18 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। महर्षि यूनिवर्सिटी की टीम ने संतुलित बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गलगोटिया की टीम ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन अंततः 18 रन से मुकाबला हार गई। जीत के साथ ही महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों और समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। अब सभी की निगाहें दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, जिसमें वेंकटेश्वर कॉलेज और बैनेट यूनिवर्सिटी की टीमें आमने-सामने हैं। इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में महर्षि यूनिवर्सिटी से भिड़ेगी और खिताब की दावेदार बनेगी। फाइनल मुकाबला और भी खास होने जा रहा है, क्योंकि इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनिंदर सिंह महर्षि यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर उपस्थित रहेंगे। उनकी मौजूदगी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और टूर्नामेंट के समापन समारोह को और भी गौरवशाली बनाएगी। एमपीएल सीजन 5 ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान दिल्ली एनसीआर के 16 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच कड़े और रोमांचक मुकाबलों का मंच प्रदान किया है।

अब क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से फाइनल मुकाबले का इंतजार है, जहां इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी पर अंतिम कब्जा किस टीम का होगा, यह तय होगा।

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के लिए एक नई उम्मीद: मेक-ए-विश फाउंडेशन इंडिया

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नोएडा। मेक-ए-विश फाउंडेशन इंडिया और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ (पीजीआईसीएच) नोएडा के बीच यह साझेदारी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। बता दें कि पिछले ढाई वर्षों में, इस सहयोग ने 1500 से अधिक बच्चों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ रहे बच्चों को कंप्यूटर, लैपटॉप, साइकिल और अन्य शैक्षिक व मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उनकी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और कई बच्चों ने इस सहायता के बल पर अपनी बोर्ड परीक्षाएँ सफलतापूर्वक पास की हैं, जो इस कार्यक्रम के शैक्षणिक प्रभाव को दर्शाता है और यह पहल न केवल बच्चों को शारीरिक उपचार में मदद करती है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाकर उनके भविष्य के सपनों को पंख भी देती है। बता दे कि मेक-ए-विश फाउंडेशन इंडिया के सीईओ ध्रुव पांडेय और मैनेजर योगेंद्र यादव ने इस साझेदारी को और विस्तार देने का संकल्प लिया है और पीजीआईसीएच के निदेशक प्रो. ए. के. सिंह और डॉ. नीता राधाकृष्णन ने डोनर्स का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा समग्र समर्थन बच्चों की कैंसर देखभाल का एक अभिन्न अंग है।

सम्पादकीय

पाकिस्तान फिर पस्त

भारत की क्रिकेट टीम के मुकाबले पाकिस्तान की टीम का हारना तो तय था, लेकिन मैच इतना एकतरफा रहेगा और पाक टीम लगातार 'सरेंडर' करेगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि विश्व चैम्पियन रहे, भारत के महानायक बल्लेबाज रहे सुनील गावस्कर ने आकलन किया था कि टीम इंडिया बहुत 'सुपीरियर' है। बीते दो सालों में वह खेल के चरमोत्कर्ष पर है। उसके मुकाबले पाक टीम तभी जीत सकती है, जब टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी बहुत खराब खेलें। गावस्कर का आकलन 'सरस्वती वाणी' साबित हुआ और 'सुपीरियर' टीम ही विजयी रही। टी–20 विश्व कप के ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से मात दी। विश्व कप में भारत के खिलाफ पाक टीम की यह सबसे बड़ी, रौंददार पराजय है। अब भारत के पक्ष में जीत–हार का समीकरण 8–1 हो गया है। अर्थात भारत ने टी–20 विश्व कप में 9 में से 8वीं बार पाक टीम को हराया है। यदि विश्व कप मुकाबलों को समग्रता में देखा जाए, तो दोनों टीमों ने कुल 17 मैच खेले हैं। उनमें से 16 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं। यह आईसीसी मुकाबलों में टीम इंडिया की लगातार 16वीं जीत है। हमने अंतिम पराजय एकदिनी विश्व कप, 2023 के फाइनल में झेली थी। उसके बाद टीम इंडिया 'अपराजेय' रही है। कमोबेश टी–20 में उसने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की चैम्पियन रही टीमों को परास्त किया है और फिलहाल वह 'विश्व चैम्पियन' टीम है। टी–20 में भारत की रैंकिंग 'नंबर एक' है, जबकि पाकिस्तान 6–7वें स्थान पर है। टीम इंडिया ने कोलंबो की स्विंग, स्पिन और टर्निंग पिच पर 175 रन बनाए, जिसके नायक रहे इशान किशन। उन्होंने 40 गेंदों पर 77 रन बनाए और 10 चौके, तीन छक्के ठोंक दिए। यह टीम इंडिया के खेल की बानगी भर है।

उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' से नवाजा गया। बधाई। यह विश्व कप में पाक टीम के खिलाफ भारत का सर्वोच्च स्कोर है। इस पिच पर 150–160 रन बना कर भी विरोधी टीम को पस्त किया जा सकता है। बहरहाल पाक टीम 114 रन ही बना पाई और पूरे 20 ओवर भी खेल नहीं सकी। हमारे बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पंड्या ने 2–2 विकेट लिए और कुलदीप यादव, तिलक वर्मा के हिस्से भी 1–1 विकेट आई। यह विश्व कप में पाक टीम का तीसरा सबसे कम स्कोर है। पाकिस्तान के उस्मान खान ने ही संघर्ष करके 44 रन बनाए और अंत में शाहीन ने नाबाद 23 रन बनाए, लेकिन तब तक मैच मुी से सरक चुका था। शेष पाक टीम के बल्लेबाज बिखरते चले गए। ऐसा लग रहा था मानो किसी अंतरराष्ट्रीय टीम के सामने कोई स्थानीय स्तर की नौसीखिया टीम खेल रही हो! बाबर आजम 142–143 मैच खेल चुके हैं, बड़े मंचों पर वह लगातार नाकाम रहे हैं, उन्होंने मात्र 5 रन बनाए और अक्षर ने उन्हें बोल्ड कर दिया, लिहाजा उन्हें अब 'संन्यास' पर विचार करना चाहिए। बहरहाल भारत–पाक मैच के आंकड़े और विवरण दुनिया के सामने है, लेकिन अब 'कृत्रिम उन्माद' और 'मिथक' खत्म कर

दैनिक राशिफल

मेष: चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ।

धनार्जन होगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।

वृषभ: इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो।

मेहमानों का आगमन होगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मसम्मान बढ़ेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें।

मिथुन: का, की, कु, घ, ङ:, छ, के, को, हा।

लेन–देन में सावधानी रखें। रोजगार मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अचानक लाभ होगा।

कर्क: ही, हे, हु, हो, डा, डी, डू, डे, डो।

चोट व रोग से हानि संभव है। कुसंगति से हानि होगी। विवाद न करें। फालतू खर्च बढ़ेंगे।

सिंह: मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे।

शारीरिक कष्ट संभव है। लेन–देन में सावधानी रखें। सुख के साधन जुटेंगे। रुका हुआ धन मिलेगा।

कन्या: टो, पा, पी, पू, ष, ण:, ठ, पे, पो।

दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। आय बढ़ेगी। भोग–विलास में रुचि बढ़ेगी।

तुला: रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, ते।

कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी। पूजा–पाठ में मन लगेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। थकान रहेगी।

वृश्चिक: तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू।

चोरी, चोट व विवाद आदि से हानि संभव है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। धनार्जन होगा।

धनु: तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू।

पुराना रोग उभर सकता है। बेचैनी रहेगी। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। कानूनी बाधा दूर होगी।

मकर: भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी।

घर–परिवार की चिंता रहेगी। भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। बेरोजगारी दूर होगी। आपका सामाजिक क्षेत्र बढ़ेगा।

कुंभ: गू, गे, गो, सो, सी, सू, स, से, दा।

शत्रु परास्त होंगे। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा।

मीन: दी, दू, थ, झ, यं, दे, दो, चा, ची।

घर–परिवार की चिंता रहेगी। विवाद को बढ़ावा न दें। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जोखिम न लें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक पुरुषोत्तम पाण्डेय द्वारा मौनेक्स ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, बी-12, निकट एमएमजी अस्पताल, शंभू दयाल काम्पलेक्स, जीटी रोड, गाजियाबाद से मुद्रित एवं 498 प्रथम तल, मैत्री लेन, सैक्टर-5, वैशाली गाजियाबाद से प्रकाशित।

सम्पादक : विजय प्रकाश पाठक
Mob : 9910460742
website : www.swastiksahara.com
E-mail : swastiksaharanews@gmail.com

विधि सलाहकार
टेट्रा लीगल एलएलपी, लॉ फर्म, नई दिल्ली
मोबाइल नंबर - +91 99990 74369

City Office:
11, Maliwara, Near Pyarelal Park, Vasant Road, Ghaziabad-201001Phone : 0120-4252839

सीधे भारत मंडपम से... क्या एआई के क्षेत्र में दुनिया को पछाड़ पाएगा भारत?

नीरज कुमार दुबे

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे वैश्विक एआई सम्मेलन में दो दिन से चल रहे विचार मंथन से एक बात उभर कर आई है कि एआई के समक्ष खड़ी चुनौतियों के हल के लिए दुनिया भारत की ओर निहार रही है। देखना होगा कि सम्मेलन के अंत में दिल्ली डिक्लेरेशन से क्या निकल कर आता है। लेकिन यहां एक ओर बात की आवश्यकता महसूस हुई कि भारत को यदि इस क्षेत्र में नेतृत्व हासिल करना है तो बड़े निवेश और सरल तथा प्रभावी नीतियों की भी जरूरत है।

देखा जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई अब केवल नई तकनीक का आकर्षण नहीं रही, बल्कि यह अर्थव्यवस्था, उद्योग, ऊर्जा, नीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुकी है। दुनिया के बड़े देश इसे रणनीतिक साधन की तरह देख रहे हैं। डाटा, कंप्यूटिंग शक्ति और उन्नत चिप आज के दौर का नया तेल बन चुके हैं। ऐसे समय में भारत के सामने मूल प्रश्न यह है कि वह एआई की दौड़ में केवल उपभोक्ता बन कर रहेगा या निमार्ता और नेता की भूमिका निभाएगा। भारत ने पहले भी तकनीकी मोड़ पर सही फैसले लेकर इतिहास बदला है। नब्बे के दशक में सूचना तकनीक और सॉफ्टवेयर सेवाओं पर जोर देने से लाखों रोजगार बने, भारतीय कंपनियां दुनिया भर में छा गईं और देश को नई पहचान मिली। आज एक वैसा ही मोड़ फिर सामने है, लेकिन इस बार दांव कहीं बड़ा है। एआई न केवल सेवाओं को, बल्कि कारखानों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, दवा उद्योग, परिवहन और ऊर्जा व्यवस्था तक को बदल सकती है। यह समझना जरूरी है कि एआई एक ही तरह की चीज नहीं है। उपभोक्ता एआई, जैसे चैट टूल या मनोरंजन आधारित अनुप्रयोग, तेजी से लोकप्रिय होते हैं, पर इन पर अक्सर कुछ ही बड़ी कंपनियों का दबदबा हो जाता है। इसके विपरीत औद्योगिक एआई हर क्षेत्र के लिए अलग समाधान मांगती है। हर उद्योग का अपना डाटा, अपनी समस्या और अपना कामकाज होता है। इसलिए क्षेत्र विशेष मॉडल बनते हैं। यही भारत की ताकत बन सकती है, क्योंकि यहां उद्योगों की विविधता और पैमाना दोनों मौजूद हैं।

उदाहरण के लिए दो पहिया वाहन उद्योग को लें। भारत दुनिया के सबसे बड़े दो पहिया बाजारों में है। यह क्षेत्र रोजगार, शहरीकरण और आय वृद्धि से जुड़ा है। अब इलेक्ट्रिक दो पहिया का चलन भी बढ़ रहा है। ऐसे में एआई आधारित मांग अनुमान, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता जांच और आपूर्ति प्रबंधन से भारी लाभ हो सकता है। मशीन लर्निंग सिस्टम खराबी का पहले ही संकेत दे सकते हैं। इससे ठहराव घटता है, लागत कम होती है और उत्पादन तेज होता है। दवा उद्योग में भी अवसर विशाल हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक है, पर गुणवत्ता बनाए रखना चुनौती रहता है। एआई आधारित विजन सिस्टम उत्पादन के दौरान सूक्ष्म दोष पकड़ सकते हैं। डाटा विश्लेषण से प्रक्रिया स्थिर रखी जा सकती है। रोबोटिक ऑटोमेशन दोहराव वाले काम सुरक्षित और सटीक तरीके से कर सकता है। इससे भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी और ऊंचे मूल्य वाले बाजार खुलेंगे।

> दुनिया के बड़े देश इसे रणनीतिक साधन की तरह देख रहे हैं। डाटा, कंप्यूटिंग शक्ति और उन्नत चिप आज के दौर का नया तेल बन चुके हैं। ऐसे समय में भारत के सामने मूल प्रश्न यह है कि वह एआई की दौड़ में केवल उपभोक्ता बन कर रहेगा या निमार्ता और नेता की भूमिका निभाएगा।

लेकिन एआई की ताकत केवल सॉफ्टवेयर से नहीं आती, इसके लिए भारी कंप्यूटिंग शक्ति चाहिए, जो उन्नत चिप यानी जीपीयू से मिलती है। ये चिप बहुत महंगी होती हैं। एक उन्नत जीपीयू की कीमत लाखों रुपये तक जा सकती है। भारत ने हजारों जीपीयू लगाए हैं और डाटा केंद्र तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष डाटा केंद्रों ने बिजली ग्रिड से भारी मात्रा में बिजली ली, जो किसी बड़े शहर की मांग के बराबर बैठती है। आने वाले वर्षों में यह मांग कई गुना बढ़ सकती है। यह भारत की बढ़ती डिजिटल क्षमता का संकेत है, पर साथ ही ऊर्जा चुनौती का भी।

अगर भारत को एआई में अग्रणी बनना है तो केवल कुछ हजार जीपीयू काफी नहीं होंगे। अमेरिका आज भी इस क्षेत्र में आगे है। उसके पास विशाल डाटा केंद्र क्षमता है और वह उन्नत जीपीयू की आपूर्ति पर नियंत्रण रखता है। इसी कारण वह तकनीकी बढ़त बनाए हुए है। चीन को रोकने की रणनीति में भी चिप आपूर्ति अहम रही है। चीन ने भी इस दौड़ को बहुत पहले समझ लिया था। उसने चिप निर्माण में भारी निवेश किया। उसकी बड़ी तकनीकी कंपनियां अपने एआई चिप बना रही हैं। भले वे अभी सबसे उन्नत स्तर पर न हों, पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका में भी बड़ी तकनीकी कंपनियां खुद चिप डिजाइन में उतर चुकी हैं। ऐसे माहौल में यदि भारत केवल पुराने स्तर की चिप बनाता रह गया तो वह पीछे छूट सकता है।

तो क्या समाधान है? क्या हमें अपनी आकांक्षा घटा लेनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत अभी विकसित देशों से कम है। जैसे जैसे लोग समृद्ध होंगे, उन्हें घरों में अधिक बिजली चाहिए होगी। अगर एआई के कारण बिजली महंगी हुई तो जीवन स्तर प्रभावित हो सकता है। यह चिंता सही है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम पीछे हट जाएं। दरअसल जरूरत बड़े सोच की है। भारत को एक साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, घरेलू चिप निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा देना। इसके लिए नीति समर्थन, निवेश और कौशल विकास जरूरी है। दूसरा, ऊर्जा ढांचा मजबूत करना। नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बेहतर ग्रिड और भंडारण तकनीक पर जोर देना होगा ताकि डाटा केंद्रों की मांग पूरी हो सके।

इसके साथ ही एआई का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे। मध्यम और छोटे उद्योगों तक भी पहुंचे। इसके लिए साझा प्लेटफॉर्म, क्लाउड ढांचा और क्षेत्र विशेष समाधान जरूरी हैं। सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों को मिल कर काम करना होगा। शोध संस्थान मॉडल विकसित करें, उद्योग वास्तविक समस्याएं और डाटा दें, और सरकार नियम, प्रोत्साहन तथा अवसंरचना दे।

भारत को ऐसे नेतृत्व की भी जरूरत है जो अलग अलग पक्षों को जोड़ सके और भरोसा बना सके। एआई को नौकरी छीनने वाली नहीं, बल्कि नई क्षमता देने वाली तकनीक के रूप में समझाना होगा। कौशल प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण और शिक्षा सुधार पर जोर देना होगा। बहरहाल, अब सवाल यह है कि एआई की दिशा कौन तय करेगा? अगर भारत ने समय रहते साहसिक फैसले लिए, चिप निर्माण, ऊर्जा ढांचा और औद्योगिक एआई पर जोर दिया, तो वह केवल तकनीक का बाजार नहीं रहेगा, बल्कि दिशा देने वाला देश बन सकता है। आईटी क्रांति ने भारत को विश्व मंच पर जगह दी थी। एआई और उन्नत कंप्यूटिंग भारत को आर्थिक शक्ति और तकनीकी आत्मनिर्भरता के नए दौर में पहुंचा सकती है। अवसर हमारे सामने है। अब निर्णय और क्रियान्वयन हमारी जिम्मेदारी है।

लोकतंत्र में राइट टू रीकॉल की चर्चा जरूरी

डा. निधि शर्मा

अभी हाल में ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा द्वारा राइट टू रीकॉल मुद्दे को संसद में उठाया गया, जो वर्तमान की राजनीति और राजनीतिज्ञों की स्थिति को देखकर जरूर इस विषय पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार, लेकिन क्या तंत्र असलियत में अपना राजधर्म निभा रहा है, इसका निर्णय भी जनता को ही करना चाहिए। हमारा दायित्व सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हालांकि यह आंकड़ा भी चुनावों के दौरान औसतन 50 से 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाता। शेष बची 40 से 45 प्रतिशत जनता इसलिए वोट नहीं डालती कि उन्हें उम्मीदवार पसंद नहीं था, उन्हें वोट डालना पसंद नहीं था या वो वर्तमान के राजनीतिक हालात से खुश नहीं हैं। ऐसी कई संभावनाएं हैं जो वोट के प्रतिशत को चुनाव आयोग के कई आयोजनों के बावजूद नहीं बढ़ा पा रहा है।

बेशक वोटरों को नोटा जैसा प्रावधान दिया गया हो, लेकिन इसके अलावा राइट टू रीकॉल रूपी हथियार को मजबूती दी जाए तो जरूर लोकतंत्र जमीनी स्तर तक वोटरों की भारी भागीदारी के साथ ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगा। राइट टू रीकॉल के अधिकार के इतिहास की बात करें तो प्राचीन एथेंसवासियों में यह प्रथा प्रचलित थी। प्रत्येक वर्ष की निश्चित तिथि पर वे निष्कासन प्रक्रिया का आयोजन करते थे। इस अवसर पर सभी नागरिकों को किसी पात्र में निष्कासन योग्य व्यक्ति का नाम लिखना होता था। जिस व्यक्ति के नाम के सबसे ज्यादा पत्र मिलते थे, उसे 10 महीने के लिए शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। यह प्रक्रिया बेशक उस समय भ्रष्ट व तानाशाह प्रवृत्ति पर लगाम जरूर लगाती रहेगी। आज भी ऐसी प्रक्रिया विश्व के 24 से ज्यादा देशों में चल रही है, जिसे राइट टू रिकॉल का नाम दिया गया है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं को किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल से पहले ही निष्कासित करने का अधिकार होता है। वर्ष 1995 से ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा विधानसभाओं ने मतदाताओं को ऐसा अधिकार दे रखा है। अमेरिका के जार्जिया, अलास्का, केन्सास जैसे राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था है। जबकि वाशिंगटन में ऐसी प्रक्रिया तभी अपनाई जाती है अगर किसी प्रतिनिधि के बुरे आचरण या अपराध में शामिल होना प्रमाणित हो जाए। अगर अपने देश भारत की बात की जाए तो राइट टू रिकॉल की शुरूआत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के घोषणापत्र में सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 में की थी। उस घोषणापत्र में लिखा था कि इस गणराज्य में मतदाओं को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होगा, यदि ऐसा चाहें, अन्यथा लोकतंत्र एक मजाक बन जाएगा। भारत की आजादी के बाद वर्ष 1974 में संविधान (संशोधन) बिल जिसमें राइट टू रिकॉल के अंतर्गत विधायक व सांसदों को वापस बुलाने संबंधित बिल लोकसभा में चर्चा के लिए रखा गया, लेकिन पास नहीं हो पाया।

वहीं वर्ष 2016 में भी उस समय के सांसद वरुण गांधी ने जनप्रतिनिधित्व कानून (संशोधन) बिल के माध्यम से इस अधिकार को लागू करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। जबकि कई राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छतीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर राइट टू रिकॉल को रूपान्तरित किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता में जागरूकता न होने कारण ये कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। इस तरह के कानूनों को राजनीतिक पार्टियां भी जनता तक नहीं पहुंचाना चाहती। जाने-माने राजनीतिक विचारक जेम्स मिल का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी डर के शासन करने का अधिकार दे दिया जाए, तो वे अधिकार का प्रयोग समाज के कल्याण से ज्यादा स्वयं के स्वार्थ के लिए करते हैं। इसलिए हमें सोच समझ कर शासन जिम्मेवार लोगों के हाथ में देना चाहिए। सामाजिक तौर पर कई प्रकार की चुनौतियों भी लोकतंत्र के सामने आती हैं चाहे चुनाव आयोग के खर्च बढ ` की बात हो या उस डर से राजनीति में रुचि कम लेने की बात हो। लेकिन विस्तृत नजरिए से देखें तो यह अधिकार लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों और जनता दोनों की जवाबदेही तय करता है।

इस अधिकार के जमीनी स्तर पर आने से सबसे पहले भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को जनता नहीं चुनेगी और प्रतिनिधि जनता की सेवा और उनके कल्याण के कामों को करने के लिए जवाबदेह रहेगा। क्योंकि ये बात तो तय है कि लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए विशेषकर युवावर्ग में इसके प्रति विश्वास पैदा करना होगा। क्योंकि वोट प्रतिशत का गिरना लोकतंत्र की नींव को हिला रहा है। इस नींव की मजबूती के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर आना ही होगा। क्योंकि इस प्रकार के निर्णय दूरगामी प्रभाव डालते हैं। एक साधारण सा सवाल है कि नौकरी पर काम करते हुए समय-समय पर हमारे काम का मूल्यांकन किया जाता है। सही न होने पर विशेषकर प्राइवेट नौकरी में मात्र एक नोटिस देकर निकाल दिया जाता है। तो इस संदर्भ में क्यों नहीं? ये प्रतिनिधि तो देश व समाज की दशा व दिशा तय करते हैं। इसलिए जनता को भी जागरूक होकर सवाल पूछने चाहिए, आखिर ये सवाल हमारे भविष्य का है। लोकतंत्र को मजूबत बनाने और जन प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने के लिए भारत में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

यूरिया नीति में बदलाव, बढ़ती लागत, घटती पैदावार

देवेंद्रराज सुथार

भारतीय कृषि व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले यूरिया उर्वरक को लेकर केंद्र सरकार के हालिया निर्णय ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आदेश के तहत यूरिया की बोरी का वजन 50 किलो से घटा कर 40 किलोग्राम कर दिया गया है। इसके साथ ही यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा भी 46 से घटा कर 36 फीसद कर दी गई है। सरकार इसे सुधारात्मक कदम के रूप में पेश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस निर्णय ने किसानों की लागत बढ़ा दी है और कृषि उत्पादन तथा देश की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

यूरिया खेती में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है। गेहूं, धान और मक्का जैसी उच्च उत्पादकता वाली फसलों की उपज काफी हद तक नाइट्रोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह पौधों की बढ़वार, पत्तियों के विकास और दाने भरने की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य तत्त्व है।

ऐसे में यूरिया के स्वरूप में किया गया कोई भी बदलाव सीधे तौर पर फसलों की पैदावार, किसानों की आय और अंततः उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। सरकार के नए फैसले के बाद यूरिया की एक बोरी में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा में भारी गिरावट आई है। पहले 50 किलो की बोरी में 46 फीसद नाइट्रोजन के हिसाब से लगभग 23 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध होती थी। अब 40 किलो की बोरी में 36 फीसद नाइट्रोजन के साथ यह मात्रा घट कर केवल 14.4 किलो रह गई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसान को उतनी ही नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक यूरिया खरीदना पड़ेगा। अगर मौजूदा 270 रुपए प्रति बोरी की कीमत को आधार बनाया जाए, तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। पहले जहां किसानों को प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए लगभग साढ़े सत्रह सौ रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब वही जरूरत पूरी करने के लिए 2835 रुपए खर्च करने होंगे। यानी बिना दाम बढ़ाए ही किसानों पर करीब 37 फीसद अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। यह बोझ खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद मुश्किल भरा साबित हो सकता है।

देश में लगभग एक करोड़ साठ लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इसमें से करीब 65 फीसद भूमि की सिंचाई वर्षा पर आधारित है। यहां दलहन, तिलहन और बागवानी जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों में यूरिया की खपत अपेक्षाकृत कम होती है और कई मामलों में एक टन प्रति हेक्टेयर से भी कम रहती है। लेकिन शेष लगभग पचास लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि पर गेहूं और धान जैसी उच्च उत्पादकता वाली फसलें ली जाती हैं, जिनके लिए नाइट्रोजन की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है। मौजूदा कृषि सिफारिशों के अनुसार गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर सालाना लगभग तीन सौ किलो नाइट्रोजन की जरूरत होती है।

जबकि 46 फीसद नाइट्रोजन वाले यूरिया के हिसाब से यह आवश्यकता लगभग 620 किलो यूरिया से पूरी हो जाती थी। इसी आधार पर देश के सिंचित क्षेत्रों के लिए सालाना करीब तीन करोड़ बीस लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत आंकी जाती है। जब कुल खपत चार करोड़ मीट्रिक टन से अधिक है, तो सवाल उठता है कि बाकी यूरिया कहां जा रहा है? इस सवाल का जवाब देश में लंबे समय से चले आ रहे यूरिया के दुरुपयोग में छिपा है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि सबसिडी वाले यूरिया का एक बड़ा हिस्सा कृषि के बजाय औद्योगिक उपयोग में चला जाता है। अनुमान है कि कुल सबसिडी वाले यूरिया का लगभग एक-तिहाई, यानी एक करोड़ मीट्रिक टन से अधिक फैक्टरियों में खप जाता है। केंद्रीय बजट 2022-23 में यूरिया में सबसिडी के लिए एक लाख 32 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। यह राशि निश्चित रूप से सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालती है। मगर सवाल यह है कि इस बोझ को कम करने की कीमत किसान क्यों चुकाए। यदि आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती, तो सबसिडी का बड़ा हिस्सा बचाया जा सकता था। इसके बजाय सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे ईमानदार किसान ही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है।

इस नीति का एक और गंभीर पहलू है यूरिया की उपलब्धता और आपूर्ति संकट। पहले ही देश के कई हिस्सों में किसान बुआई के समय घंटों लंबी कतारों में लग कर यूरिया खरीदने को मजबूर हैं। कई बार समय पर पूरी मात्रा नहीं मिल पाती। इससे खाद डालने का सही समय निकल जाता है। अब जब प्रति हेक्टेयर जरूरत पूरी करने के लिए अधिक बोरियां खरीदनी पड़ेंगी, तो यह संकट और गहराने की आशंका है। इसका सीधा असर फसलों के विकास और अंततः पैदावार पर पड़ेगा।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की पूरी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 120 से 150 किलो नाइट्रोजन की जरूरत होती है। पहले किसानों को यह मात्रा प्राप्त करने के लिए 50 किलो वाले यूरिया की लगभग सात बोरियां डालनी पड़ती थी। अब वही मात्रा पाने के लिए उसे दस से ग्यारह बोरी यूरिया की जरूरत होगी। इससे न केवल लागत बढ़ेगी, बल्कि मिट्टी के संतुलन और पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। यह संकट केवल किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देश की खाद्य सुरक्षा से भी है। पिछले तीन वर्षों में गेहूं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद सरकारी खरीद अपने लक्ष्य से काफी पीछे रही है। यह स्थिति तब है, जब सरकार पैदावार के बड़े-बड़े दावे करती रही है। इस विरोधाभास से संकेत मिलता है कि देश में गेहूं का वास्तविक उत्पादन और घरेलू खपत लगभग बराबर स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में यदि यूरिया की कमी या महंगाई के कारण पैदावार में गिरावट आती है, तो देश को अनाज आयात पर निर्भर होना पड़ सकता है। खाद्य सुरक्षा किसी भी देश की संप्रभुता और सामाजिक स्थिरता का आधार होती है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में अनाज उत्पादन में थोड़ी-सी भी कमी व्यापक प्रभाव डाल सकती है। महंगाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव और ग्रामीण असंतोष इसके संभावित परिणाम हो सकते हैं। इसलिए यूरिया जैसी बुनियादी कृषि सामग्री को लेकर तय की गई किसी भी नीति का मूल्यांकन केवल बजट संतुलन के नजरिए से नहीं किया जाना चाहिए। समाधान के रास्ते मौजूद हैं, बशर्ते नीति-निर्माण में इच्छाशक्ति और व्यावहारिक दृष्टिकोण हो। सबसे पहले यूरिया के औद्योगिक दुरुपयोग पर सख्ती से रोक लगानी होगी। किसानों के लिए उपलब्ध यूरिया की गुणवत्ता और मात्रा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

नीतियां जमीनी वास्तविकताओं और वैज्ञानिक सिफारिशों के अनुरूप होनी चाहिए, न कि केवल कागजी आंकड़ों पर। यह समझना होगा कि किसान, कृषि और खाद्य सुरक्षा एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक को कमजोर कर बाकी दो को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा का आधार भी है। ऐसे में कोई भी प्रयोग दूरगामी परिणाम लेकर आता है। यदि किसान लागत बढ़ने या उपलब्धता की कमी के कारण आवश्यक मात्रा में यूरिया नहीं डाल पाता, तो उपज में गिरावट तय है।

सेहत/स्वास्थ्य

सिक्के जैसे गोल पैच में झड़ रहे हैं बाल? विशेषज्ञों से जानें एलोपेसिया के लक्षण और उपचार

अक्सर आपने ऐसे व्यक्ति को जरुर देखा होगा कि जिसके सिर या दाढ़ी में गोल पैच हों? एक ही जगह से अचानक से सारे बाल झड़ गए हों। दरअसल, यह एलोपेशिया एरियाटा' हो सकता है। यह एक प्रकार से ऑटोइम्यून हेयर लॉस कंडीशन है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से हेयर फॉलिकल्स को दुश्मन मानकर उसे नुकासान पहुंचाने लगता है। इस कंडीषसन के कारण सिर से गोल-गोल पैचेज में बाल झड़ने लगते हैं। यह आइब्रो, दाढ़ी और शरीर के सभी अंगों के बालों को भी प्रभावित करते हैं।

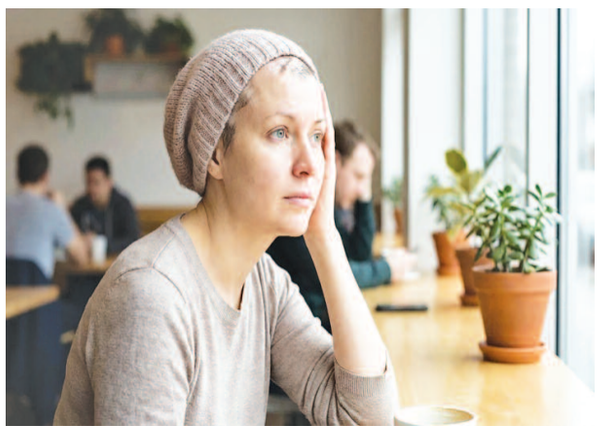

एलोपेशिया एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से हेयर फॉलिकल्स पर हमला कर देता है, जिससे सिर, दाढी या शरीर पर गोल पैच में अचानक बाल झडने लगते हैं। इसके इलाज के लिए डॉक्टर इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने वाली दवाएं देते हैं, साथ ही तनाव प्रबंधन और संतुलित आहार भी अहम भूमिका निभाते हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के रिचर्स के मुताबिक, पूरी दुनिया में करीब 2% लोग जीवन में कभी न कभी एलोपेशिया से प्रभावित होते हैं। अमेरिका में ही करीब 68 लाख लोग इस कंडीशन का सामना कर रहे हैं। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

क्या है एलोपेशिया?

असल में एलोपेशिया एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही हेयर फॉलिकल्स (बालों की जड़) पर हमला करने लगता है। इसी वजह से अचानक से बाल झड़ने लगते हैं और गोल या पैची गंजापन दिखने लगते हैं। बता दें कि, यह समस्या कॉस्मेटिक समस्या नहीं, बल्कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। इतना ही नहीं, इस कंडीशन में बालों की जड़ स्थायी रूप से नष्ट नहीं होती, बल्कि अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाती है।

एलोपेशिया के शुरूआती लक्षण क्या हैं?

एलोपिशिया में अचानक से बाल झड़ने लगते हैं, खासकर के सिक्के के आकार में पैच में। कंघी करते या नहाते समय बाल गुच्छों में झड़ते हैं।

स्कैल्प में खुजली होना, हल्की जलन या झुनझुनी महसूस होना। नाखूनों पर गड्ढे, खुरदरापान या सफेद धब्बे भी दिख सकते हैं। शुरूआत में दर्द नहीं होता है। इसलिए लोग इसे सामान्य हेयर फॉल को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। हालांकि समय पर बीमारी की शिनाख्त इलाज को ज्यादा कारगर बना सकती है। नहाते समय बाल झड़ना, भौंह, पलक, दाढ़ी के बाल झड़ना और स्कैल्प में पैचेज बनना

एलोपेशिया होने के संभावित करण

वैसे तो एलोपेशिया का मुख्य कारण इम्यून सिस्टम का असंतुलन है। इसके पीछे जेनेटिक कारण, तनाव, वायरल इंफेक्शन, हॉर्मोनल बदलाव और अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों जिम्मेदार हो सकती हैं।

न्यूट्रिशन की कमी के कारण एलोपेशिया हो सकता है। इसके अलावा, क्रॉनिक स्ट्रेस व क्रॉनिक इन्फेक्शन, या फिर कोई फ्रॉनिक बीमारी और दवाओं के साइड इफेक्ट भी हो सकता है।

एलोपेशिया का इलाज क्या है?

एलोपेशिया का इलाज उसकी स्थिति और गंभीरता के अनुसार तय किया जाता है। आमतौर पर डॉक्टर ऐसी दवाएं देते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें, जैसे स्टेरॉइड युक्त क्रीम, इंजेक्शन या अन्य औषधियां, जिससे बालों की दोबारा वृद्धि में सहायता मिल सके। कुछ गंभीर मामलों में इम्यूनोथेरेपी या ओरल दवाओं का भी सहारा लिया जाता है। इसके अलावा संतुलित आहार, तनाव कम करना और पर्याप्त नींद लेना भी उपचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये सभी कारक बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

क्या घरेलू या नेचुरल उपाय एलोपेशिया के इलाज में मदद करते हैं?

वैसे तो घरेलू या नेचुरल उपाय एलोपेशिया का इलाज नहीं, हालांकि सहायक भूमिका निभा सकता है-

आप संतुलित आहार, प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन-डी की पर्याप्त मात्रा जरुरी है। इसके अलावा, आप रोजाना योग, ध्यान और स्ट्रेस मैनेजमेंट इम्यून बैलेंस में मदद कर सकते हैं। प्याज का रस, एलोवेरा या नारियल तेल स्कैल्प की हेल्थ सुधार सकते हैं, लेकिन ये इम्यून अटैक को नहीं रोकते हैं।

ब्यूटी / फैशन

आयुर्वेद का एंटी-एजिंग सीक्रेट: ये 5 फूड्स लौटाएंगे चेहरे का नेचुरल ग्लो

बढ़ती हुई उम्र को रोप पाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को जवां जरुर रख सकते हैं। ऐसे में हर एक महिला का सपना होता है कि एजिंग को रोकना और चेहरे को ग्लोइंग बनाना। हालांकि महंगी क्रीम, सीरम और फेशियल केवल बाहरी तौर पर असर करते हैं। लंबे निखार के लिए आपके शरीर को अंदर से पोषण मिलना भी जरुरी है। अगर आपका चेहरा भी डल दिखाई है, चेहरे की चमक कहीं खो गई है या फिर बढ़ती उम्र का असर चेहरे की निखार को खा गया है, तो आप आयुर्वेदिक तरीके से अपने स्किन को नेचुरल ग्लोइंग बना सकती हैं। आप अपने खाने में ये 5 सुपरफूड्स को शामिल कर सकते हैं।

जवां और चमकदार त्वचा के लिए आंतरिक पोषण आवश्यक है; जानें कैसे केसर, अनार, और देसी घी जैसे 5 सुपरफूड्स को डाइट में शामिल कर एजिंग को धीमा करें और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाएं।

केसर वाला दूध

कई सदियों से केसर का इस्तेमाल त्वचा की रंगत के लिए किया जा रहा है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खून को साफ करते हैं और चेहरे पर ग्लो लेकर आता है।

कैसे पिएं केसर वाला दूध?

- रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 3-5 केसर के रेशे डालें और फिर इसको पिएं।

- नियमित तौर पर केसर वाला दूध पीने से स्किन नेचुरली ग्लो देती, गहरी और सुकून वाली नींद आती है।

एंटी-एजिंग का पावरहाउस अनार

अनार का सेवन के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यह 'फलों का गहना' माना जाता है। इसमें पॉलीफेनोल्स होते हैं, जो सूरज की हानिकारक किरणों से त्वचा को बचाते हैं और झुर्रियों को आने से रोकते हैं। अनार खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे गालों पर नेचुरली गुलाबी निखार आता है।

अनार को कैसे डाइट में लें?

- रोजाना आधा कप ताजे अनार के दाने जरुर खाएं।

- जूस पीने से बेहतर है कि आप अनार के दाने खाएं। ऐसा करने से आपकी स्किन को फाइबर मिलता है।

देसी घी

हमारे दादी-नानी ने खूब घी खाया, जिससे उनकी स्किन के साथ ही बॉडी भी स्ट्रांग रही है। आयुर्वेद में घी को अमृत माना गया है। यह त्वचा को अंदर से नमी देता है और ड्राई होने से बचाता है। घी के सेवन से चेहरे पर हेल्दी ग्लो आता है।

देसी घी कैसे लें?

दिनभर में 1 छोटा चम्मच देसी घी अपनी दाल या रोटी में डालकर खाएं। हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया है कि, अगर आप रात में गर्म दूध में घी मिलाकर पिएंगे, तो आपकी त्वचा और जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है।

ग्लोइंग त्वचा के लिए डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनोल्स होते हैं जो त्वचा में ब्लड सकुर्लेशन को बढ़ाते हैं और स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं। यह तनाव को कम करती है, जिससे आपके चेहरे पर सकारात्मक असर देखने को मिलता है।

डार्क चॉकलेट कैसे लें?

दिन में एक बार डार्क चॉकलेट का छोटा टुकड़ा (कम से कम 10-15 ग्राम) लें। ध्यान रहे कि चॉकलेट में कोकोओ की मात्रा 70 प्रतिशत से ज्यादा हो।

विटामिन-अ का खजाना शकरकंद

शकरकंद हेल्थ नजरिए से काफी फायदेमंद होती है। इसमें बीटा-कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे शरीर में विटामिन-अ (रेटिनॉल) में बदल जाता है। यह स्किन सेल्स को नया बनाने और उम्र के लक्षण को कम करने में मदद करती है।

शकरकंद कैसे लें?

दिन में किसी भी समय आधा कप उबली हुई या भूनी हुई शकरकंद जरुर खाएं। यह आपकी स्किन को टाइट और ग्लोइंग रखने में मदद करता है।

पर्यटन

सस्ते में घूमें पूरा राजस्थान: आईआरसीटीसी के इस पैकेज में 12 दिन का ट्रिप, देखें पूरी लिस्ट

> आईआरसीटीसी कोलकाता से 12 रात/13 दिन का 'रॉयल राजस्थान' टूर पैकेज लाया है, जिसकी शुरूआती कीमत लगभग 30 हजार रुपये है; इस पैकेज में ट्रेन यात्रा, होटल और नाश्ते के साथ जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे शहर शामिल हैं।

क्या आप भी राजस्थान का टूर करना चाहते हैं? अब आप 30 हजार रुपये के अंदर राजस्थान घूमने का मौका मिल रहा है। दरअसल, भारतीय रेलवे टूर पैकेज लेकर आया है, जिसमें आप पूरा राजस्थान घूम सकते हैं। आपतो बता दें कि, 12 दिनों का यह टूर पैकेज है, जिसकी शुरूआत कोलकाता से होगी। इसका अर्थ है कि कोलकाता के लोग इस पैकेज से राजस्थान घूम सकते हैं। यदि आप अपने परिवार के साथ लंबी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, तो यह टूर पैकेज आपके लिए है। आइए आपको बताते हैं इस पैकेज के बारे में-

12 दिन का टूर पैकेज कब से हो रहा है शुरू?

- इस पैकेज की शुरूआत कोलकाता से हो रही है।
- इसमें आपको जयपुर, अजमेर, पुष्कर, उदयपुर और जोधपुर घूमने का अवसर मिलेगा।
- यह पैकेज 12 रात और 13 दिनों का है।
- इस पैकेज के लिए आप हर शनिवार टिकट बुक कर सकती हैं।
- इस पैकेज के जरिए आपको ट्रेन से यात्रा करवाया जाएगा और घूमने के लिए कैब की सुविधा मिलेगी।
- आप इस पैकेज का नाम सर्च कर सकते हैं। टूर पैकेज का नाम है ROYAL RAJASTHAN WITH CONFIRMED TRAIN TICKET EX KOLKATA है।
- पैकेज का कोड EHR137 है।

पैकेज फीस किस तरह से तय की गई है?

- 2 लोग ट्रैवल करने पर पैकेज की फीस ज्यादा है। इसमें आपको 42460 रुपये देने होंगे।
- यदि आप 3 लोगों के साथ में यात्रा कर रहे हैं, तो पैकेज फीस कम है। 3 लोगों के लिए आपको 33780 रुपये है।
- प्रति व्यक्ति पैकेज फीस भरना होगा, हर व्यक्ति को अलग-अगल 33780 रुपये देने होंगे।
- वहीं, बच्चों के लिए पैकेज फीस 16415 रुपये हैग्र

पैकेज में मिलने वाली सुविधाएं

- 3AC/SL श्रेणी ट्रेन टिकट बुक करने का ऑप्शन मिलेगा।
- स्लीपर का पैकेज फीस सस्ता है।
- इस पैकेज में होटल में ठहरने की व्यवस्था मिल रही है।
- सभी परिवहन और दर्शनीय स्थलों की यात्रा निजी वाहन द्वारा होगी।
- आपको भोजन में सिर्फ नाश्ता दिया जाएगा।
- भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट से टिकट बुकिंग का तरीका आसान है।

पैकेज में नहीं मिलने वाली सुविधाएं

- अगर आप पैकेज के अलावा कोई और भी सुविधा लेंगी तो आपको अलग से पैसे देने होंगे।
- मिनरल वाटर, रूम हीटर, शीतल और कठोर पेय और पोर्टर शुल्क जैसी कोई भी सुविधा होटल में लेने पर फीस अलग से देनी होगी।
- आपको दर्शनीय स्थल पर एंट्री फीस के लिए अलग से देने होंगे।
- गाइड शुल्क, हाथी की सवारी, ऊंट की सवारी और घोड़े की सवारी का खर्च पैकेज फीस में शामिल नहीं है।
- ट्रेन का भोजन नहीं मिलेगा।
- इसके अलावा, एचडब्ल्यूएच पर पिक-अप और ड्रॉप सुविधा नहीं मिलेगी।

घरेलू नुस्खे

सेहरी स्पेशल: सिर्फ 10 मिनट में बनाएं ये टेस्टी-हेल्दी डिश, रमजान में नहीं होगी कमजोरी

रमजान में रोजे के दौरान कमजोरी से बचने के लिए सहरी का पौष्टिक होना जरूरी है। यह लेख 10 मिनट में बनने वाली कुछ आसान और हेल्दी रेसिपीज जैसे ओट्स उपमा, बेसन चीला और खजूर स्मूदी के बारे में बताता है, जो आपको दिनभर ऊर्जावान बनाए रखेंगी।

रमजान इस्लाम का पवित्र महीना है। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना-पीना त्यागते हैं। यह आत्मसंयम, धैर्य और ईश्वर की इबादत का समय होता है। इस दौरान लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान का पाठ करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। रमजान के अंत में ईद-उल-फितर मनाई जाती है। इस दौरान सहरी का विशेष महत्व माना जाता है, यह पूरे दिन रोजे के लिए भोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनता है। गौरतलब है कि महिलाओं को बड़ी दुविधा होती है कि सहरी में क्या बनाया जाए, जो काफी हेल्दी हो और पौष्टिक भी हो।

रमजान में सुबह जल्दी उठकर सीमित समय में स्वाद और सेहत का संतुलन बनाना काफी मुश्किल होता है। अगर आप सेहरी में ऐसे व्यंजन को बनाएं, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और ऊर्जा से भरपूर हों। इस लेख में हम आपको बताएंगे आसान और झटपट तरीके से बनने वाले टेस्टी ऑप्शन, जो आपके सेहरी के लिए एकदम परफेक्ट साबित होंगे।

वेज ओट्स उपमा

इसे बनाने के लिए एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म कर लें। अब इसमें राई, करी पत्ता और बारीक कटी हरी मिर्च डालें। अब गाजर, मटर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां डालकर हल्का भून लें। इसके बाद अलग से सूखे ओट्स हल्का भून लें और फिर सब्जियों में मिला लें। अब आप स्वादानुसार नमक और थोड़ा पानी डालकर 3-4 मिनट ढककर पकाएं। आखिर में ऊपर से नींबू का रस डालकर गरमागरम परोसें।

बेसन चीला

सबसे पहले एक बाउल में बेसन डालें और उसमें स्वादानुसार नमक, थोड़ी हल्दी, अजवाइन तथा बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर मिलाएं। अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालते हुए चिकना और थोड़ा पतला घोल तैयार कर लें। इसके बाद तवा गरम करें और उस पर हल्का सा तेल लगा दें। तैयार घोल को तवे पर डालकर गोल आकार में फैलाएं और मध्यम आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें। तैयार चीला हरी चटनी या दही के साथ गरमागरम परोसें।

मूंग दाल चीला

मंगू दाल का चीला बनाने के लिए आप सबसे पहले भीगी हुई मूंग दाल को पीसकर पेस्ट बना लें। इसमें अदरक, हरी मिर्च और नमक डालें। अब तवे पर हल्का तेल डालकर घोल फैलाएं। फिर इसे दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक पकाएं। अब चाहे तो इसमें अंदर थोड़ा पनीर भरकर डाल सकती हैं।

एग भुर्जी

सबसे पहले कड़ाही में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें, फिर कटे हुए टमाटर मिलाकर नरम होने दें। अब इसमें स्वादानुसार हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद फेंटे हुए अंडे कड़ाही में डालें और मध्यम आंच पर लगातार चलाते रहें ताकि अंडे अच्छी तरह पककर दानेदार बन जाएं। लगभग 2-3 मिनट में स्वादिष्ट अंडा भुर्जी तैयार हो जाएगी। ऊपर से हरा धनिया छिड़ककर गरमागरम रोटी के साथ परोसें।

आलू पराठा

उबले आलू मैश करें। फिर इसमें नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा गरम मसाला मिलाएं। आटे की लोई बनाकर इसमें आलू का मिश्रण भरें और बेल लें। तवे पर घी या तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें। फिर इसको दही के साथ परोसें।

खजूर और केला स्मूदी

मिक्सर में 1 केला, 3-4 खजूर (बीज निकाले हुए), एक गिलास दूध और थोड़े भीगे हुए बादाम डालें। अब इसको अच्छे से पीस लें। फिर इसको आप ठंडा सर्व करें। यह स्मूदी सहरी में आपको काफी ऊर्जा प्रदान करेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा हुआ मजबूत, बीमारू से उत्तम प्रदेश बना यूपी

पिछले नौ वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ व्यापक विस्तार, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सीएचसी व पीएचसी की संख्या बढ़ी

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

लखनऊ। योगी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में व्यापक सुधार किए हैं। प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। साथ ही इन केंद्रों को आधुनिक उपकरणों, पर्याप्त दवाओं और विशेषज्ञ चिकित्सकों से सुसज्जित किया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ केंद्रों पर 24 घंटे मिल रही प्रसव, पैथोलॉजी, एक्स-रे की सुविधा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में कमान संभालने के बाद प्रदेश में सैकड़ों नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के साथ उच्चीकृत भी किए हैं। जहां पहले कई पीएचसी में नाममात्र की सुविधाएं थीं, वहीं अब उनमें 24 घंटे प्रसव सुविधा, पैथोलॉजी जांच, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष प्राथमिकता देते हुए संस्थागत प्रसव दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। योगी सरकार की प्राथमिकता 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल मंत्र के साथ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूत किया गया। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को तेज किया गया जिससे लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरा जा सका। साथ ही संविदा और नियमित नियुक्तियों के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता भी बढ़ाई गई।

संचारी रोगों की रोकथाम के लिए मजबूत किया डिजिटल सर्विलांस सिस्टम

प्रदेश में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए डिजिटल सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया गया है।

डेंगू, मलेरिया, एईएस और जेई जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्राथमिक स्तर पर ही जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जांच प्रयोगशालाओं की संख्या में कई गुना वृद्धि की गई है, जिससे रोगों की शीघ्र पहचान और समय पर उपचार संभव हो पाया है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पिछले वर्षों में कई जिलों में मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से लाखों पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वास्थ्य कार्ड वितरण और लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया को भी डिजिटल माध्यम से पारदर्शी बनाया गया है।

विशेषज्ञ की राय

पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे में जो परिवर्तन हुए हैं, वे जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। सीएचसी और पीएचसी को 24 घंटे प्रसव, पैथोलॉजी और एक्स-रे जैसी सुविधाओं से सुसज्जित करना ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। डिजिटल सर्विलांस और लैब नेटवर्क के विस्तार से संचारी रोगों की समय पर पहचान और नियंत्रण संभव हुआ है। टेलीमेडिसिन और ई-संजीवनी जैसी पहल ने दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को विशेषज्ञ सेवाओं से जोड़ा है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट और टीकाकरण कवरेज में सुधार इस बात का संकेत है कि प्राथमिक स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता सकारात्मक परिणाम दे रही है।

डॉ. लिली सिंह, पूर्व डीजी, स्वास्थ्य विभाग

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ने से आमजन को राहत मिली

स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरूआत से दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध हो रहा है। ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से हजारों मरीज घर बैठे चिकित्सकीय सलाह प्राप्त कर रहे हैं। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत हुई है, बल्कि ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा भी सुलभ हुई है। योगी सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया गया था, वह अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। आधुनिक मशीनों की उपलब्धता, प्रशिक्षित स्टाफ, दवा आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था और डिजिटल निगरानी प्रणाली ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को नई ऊंचाई दी है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ने से आमजन को राहत मिली है और प्रदेश एक सशक्त, स्वस्थ और विकसित राज्य की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

टीकाकरण में देश में अग्रणी स्थान किया प्राप्त

प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ मेडिकल शिक्षा पर भी जोर दिया है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण से विशेषज्ञ सेवाओं का दायरा बढ़ा है। इससे प्राथमिक स्तर पर मरीजों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें उच्च संस्थानों में रेफर करने की व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस सेवाओं 102 और 108 को सशक्त किया गया है, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को शीघ्र उपचार मिल सके। कोविड-19 महामारी के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। गांव-गांव में स्वास्थ्य टीमों ने स्क्रीनिंग, जांच और टीकाकरण अभियान चलाया। प्रदेश ने टीकाकरण के मामले में देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया, जिनका लाभ आज भी सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में मिल रहा है।

सहकार से समृद्धि : एम-पैक्स से 54 लाख किसान बने आत्मनिर्भर

योगी सरकार ने महाअभियान चलाकर सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया फसली ऋण, उन्नत बीज और उर्वरक

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

लखनऊ। प्रदेश में सहकारिता आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में योगी सरकार के एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान का व्यापक परिणाम दिख रहा है। अभियान के जरिए अब तक करीब 54 लाख किसान सहकारी ढांचे से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़े हैं। योगी सरकार का फोकस बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (एम-पैक्स) से लोगों को जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती वित्तीय और कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

गांवों में ऋण प्रवाह बढ़ा और छोटे किसानों को मिली सहूलियतें

योगी सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत किसानों को कम ब्याज दरों पर फसली ऋण, उन्नत गुणवत्ता के बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए गए। इससे खेती की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से जिला सहकारी बैंकों में दो लाख से अधिक नए खाते खोले गए हैं।

इन खातों में अब तक लगभग 550 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई जा चुकी है। वहीं, सदस्यों की भागीदारी से 110 करोड़ रुपये की अंश पूंजी जुटाई गई जिसके आधार पर कुल 660 करोड़ रुपये की धनराशि सहकारी तंत्र में प्रवाहित हुई। इससे गांवों में ऋण प्रवाह बढ़ा है और छोटे किसानों को सहूलियतें आसान हुई हैं।

ग्रामीणों को घर के पास ही पंजीकरण और अन्य सेवाएं

योगी सरकार ने सहकारी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए सदस्यता प्रक्रिया को भी पूरी तरह डिजिटल किया है।

अब एम-पैक्स से जुड़ने के लिए डिजिटल पोर्टल और मोबाइल आधारित पंजीकरण की सुविधा लागू कर दी गई है। इससे ग्रामीणों को घर के पास ही पंजीकरण और अन्य सेवाएं मिल रहीं हैं।

देश में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम-पैक्स का सदस्यता महाअभियान शुरू किया। यह सदस्यता महाअभियान दो चरणों में चलाया गया। पहले चरण की शुरूआत सितंबर 2023 में की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर नए सदस्य जुड़े। दूसरे चरण का शुभारंभ सितंबर 2025 में किया गया, जिसमें अभियान को और गति मिली।

डिजिटल भुगतान से आई पारदर्शिता

सहकारी समितियों को मजबूत करना योगी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। एम-पैक्स पर डिजिटल भुगतान प्रणाली क्यूआर कोड के जरिए शुरू की गई है। क्यूआर कोड और यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू हो जाने से कैशलेस एवं पारदर्शी भुगतान व्यवस्था लागू हुई है। इससे उर्वरक वितरण में पारदर्शी एवं सुविधाजनक तरीके से वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि सहकार से समृद्धि का लक्ष्य तेजी से हासिल किया जा सके।

प्रज्ञान स्कूल के छात्रों की जेईई मेन 2026 में उल्लेखनीय सफलता

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

जेवर। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर के मेधावी छात्रों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स 2026 सत्र 1 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार विद्यालय के छात्र पीयूष कुमार, लक्ष्य गोयल एवं हितेश कुमार ने शानदार सफलता प्राप्त की है। छात्र पीयूष कुमार (सामान्य वर्ग) ने 98.1683710 पर्सेंटाइल अर्जित कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं लक्ष्य गोयल (सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग) ने कुल 87.3029450 पर्सेंटाइल प्राप्त किए। साथ ही हितेश कुमार (ईडब्ल्यूएस वर्ग) ने 82.85 पर्सेन्टाइल प्राप्त कर सफलता पाई है।तीनों छात्रों की यह उपलब्धि उनके कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। विद्यालय में इस सफलता से हर्ष और उत्साह का वातावरण व्याप्त है।शिक्षकों एवं सहपाठियों ने दोनों छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय की प्रधानाचार्या डा. दीप्ति शर्मा ने छात्रों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह सफलता उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को भी इनसे प्रेरणा लेने का संदेश दिया।विद्यालय के प्रबंधक डा. हरीश कुमार शर्मा ने भी छात्रों को हार्दिक बधाई दी और कहा कि विद्यालय सदैव विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं उच्च स्तरीय मार्गदर्शन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये छात्र भविष्य में भी नई ऊँचाइयों को स्पर्श करेंगे।

क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत विवेकानंद स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन और स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

गाजियाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत, नंदग्राम स्थित सेवाभारती द्वारा संचालित विवेकानंद स्कूल में क्षय रोग जागृति हेतु एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के लगभग 200 बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही सुंदर चित्रण किया, जिसने सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अनिल यादव ने सभी चित्रकारों की मुक्त कंठ से प्रसंशा की इनर व्हील क्लब गाजियाबाद ग्रेटर की अध्यक्ष सुषमा गुप्ता ने सभी बच्चों को उपहार देकर प्रोत्साहित किया'

स्वस्थ जनपद की संरचना में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद, जिला क्षय रोग विभाग व जिला स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से एक बृहद स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम (दवा सहित)भी सुबह से ही आयोजित किया गया, जिसमें करीब 100 व्यक्तियों के टी. बी.उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ऑन द स्पॉट छाती के एक्सरे भी किए गए। डॉक्टर ने गहन अध्ययन करने के बाद बताया कि करीब तीन से चार लोगों को टीबी का रोग सस्पेक्टेड है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सभापति सुभाष गुप्ता का मानना था कि इस तरह के गरीब सेवा बस्तियों में पहुंचकर ही हम टीबी मुक्त भारत की कल्पना को धरातल पर उतार सकते हैं।

सभापति सुभाष गुप्ता के अथक प्रयासों से ही अब तक लगभग 5,000 पोषण पोटली का वितरण जिले के विभिन्न स्थानों पर श्रेणी बद्ध तरीके से कैंप लगाकर टीवी पेशेंट को प्रोटीनयुक्त अनाजों की पोषण पोटली डाइट स्वस्थ डायट के तहत दी जा चुकी हैं। इन पोषण पोटली को देने के लिए गाजियाबाद के विभिन्न सामाजिक संगठनों के अलावा गाजियाबाद के रोटरी क्लब एवं गाजियाबाद के इनरव्हील क्लब की विशेष भूमिका रही है।

सभापति सुभाष गुप्ता ने अपनी टीम के सेवा संकल्प को देखते हुए विश्वास के साथ बताया कि अगले कुछ वर्षों में हमारा जनपद पूर्ण रूप से टीबी मुक्त हो जाएगा।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि को उन्होंने रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब के सदस्यों को समर्पित भी किया तथा कहा कि उनके समर्पण से हम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से तथा विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टर के सहयोग से हम जिले के एक-एक टीबी पेशेंट तक पहुंच रहे हैं।

इस अवसर पर, इनर व्हील क्लब ग्रेटर गाजियाबाद की अध्यक्ष ने कहा कि हम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें खुशी है कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सके और बच्चों को प्रोत्साहित कर सके। संजय यादव, एम. सी. गौड़, अश्वनी शर्मा, आर. डी. शर्मा, विपिन अग्रवाल, अरुण गुप्ता, सीमा भसीन ने संयुक्त रूप से कहा कि हम सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं।

विराट हिंदू सम्मेलन में हिन्दुत्व की जय-जयकार: लेखिका चित्रा गर्ग ने जगाई अलख

स्वास्तिक सहारा ब्यूरो

नई दिल्ली। ईस्ट ऑफ कैलाश में आयोजित ह्यविराट हिंदू सम्मेलनह्ल में आज हिंदू समाज की एकजुटता का एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें बच्चों से लेकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों तक, हर पीढ़ी ने बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराई। सम्मेलन के दौरान बालिकाओं ने देशभक्ति और भारतमाता की वन्दना पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर समां बांध दिया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण एक 4 वर्षीय बालक रहा, जिसने पूरा हनुमान चालीसा सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही कार्यक्रम में शबद कीर्तन की भी गरिमामयी प्रस्तुति हुई।

लेखिका चित्रा गर्ग का विशेष सम्मान

ईस्ट ऑफ कैलाश में सकल हिंदू समाज की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में सुप्रसिद्ध लेखिका चित्रा गर्ग का विशेष अभिनंदन किया गया। आयोजक मंडल ने उन्हें पटका पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। पूरे आयोजन के दौरान समाज में समरसता, एकता और सामाजिक सौहार्द का संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

चित्रा गर्ग के ओजस्वी विचार

अपने संबोधन में चित्रा गर्ग ने हिंदुत्व की प्रासंगिकता को बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से समझाया। उन्होंने कहा: 'हिंदुत्व केवल एक पहचान नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गौरवशाली पद्धति है।'

साहित्य के जरिए वैचारिक जागृति

समाज में वैचारिक चेतना लाने के उद्देश्य से चित्रा गर्ग ने अपनी लिखी कुछ देशभक्ति की पुस्तकों का वितरण भी किया। उन्होंने लोगों से अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहने का आह्वान किया। उनकी पुस्तकों को देखकर उपस्थित जनसमूह में भारी उत्साह और जोश देखने को मिला।

प्रमुख हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कपिल खन्ना और राजेश बिरमानी (फरर) जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उन्होंने समाज को संगठित होने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सभा अध्यक्ष एम. एल. धवन, आदर्श महेन्दू, पवन शर्मा और धर्मवीर चौधरी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

प्रौद्योगिकी से सशक्त हुई एमएसएमई: योगी सरकार ने यूपी को बनाया डिजिटल औद्योगिक शक्ति केंद्र

उद्यम सारथी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आसान हो रहा कारोबार, एमएसएमई चैम्पियनशिप और तकनीकी उन्नयन से बढ़ी प्रतिस्पर्धा

स्वास्तिक सहारा नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को प्रौद्योगिकी से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बहुस्तरीय पहल की गति तेज कर दी हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तकनीकी उन्नयन और नीतिगत सुधारों के माध्यम से प्रदेश के 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को प्रतिस्पर्धी और बाजारोन्मुख बनाने का प्रयास किया गया है। योगी सरकार के इन कदमों से उत्पादन क्षमता बढ़ी है और रोजगार सृजन को नई गति प्राप्त हुई है।

डिजिटल अवसंरचना, नीतिगत सरलता और वित्तीय सहयोग के संयोजन ने प्रदेश को अग्रणी औद्योगिक केंद्र बनाने की आधारभूमि को तैयार करने का काम किया है। एमएसएमई सेक्टर की योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार के बजट 2026-27 में 3,822 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है।

ओडीओपी को मिला डिजिटल आयाम

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत मार्केटिंग डेवलपमेंट, टूलकिट वितरण और प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसके माध्यम से एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के कारीगरों को तकनीक आधारित कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पारंपरिक उत्पादों को ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने से स्थानीय वस्तुओं की पहुंच राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक बढ़ी है।

एमएसएमई चैम्पियनशिप इनीशिएटिव (चैंपियंस पोर्टल) के अंतर्गत चयनित इकाइयों को आधुनिक मशीनरी को अपनाने, गुणवत्ता सुधार और डिजिटल टूल्स के उपयोग के लिए तकनीकी सहायता दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य उत्पादन लागत को घटाकर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और विकसित करना है। लाखों इकाइयों को डिजिटल उन्नयन और विपणन सहयोग का लाभ मिल रहा है।

उद्यम सारथी और आरएएमपी का सहारा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2021 को लॉन्च की गई उद्यम सारथी ऐप के जरिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन, योजनाओं की जानकारी और संचालन मार्गदर्शन एक ही मंच पर उपलब्ध कराया गया है। इससे उद्यमियों की सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों तक त्वरित पहुंच प्राप्त हो जाती है। प्रदेश में आरएएमपी (राइजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफार्मेंस) योजना विश्व बैंक समर्थित एक केंद्रीय पहल है, इसके अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी समर्थन भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण को बल मिला है।

नीतिगत सरलता और त्वरित संचालन

वर्ष 2022 से लागू एमएसएमई नीति के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। प्लग एंड प्ले मॉडल से 72 घंटे में संचालन शुरू करने की सुविधा दी गई है। क्रेडिट प्रवाह में वृद्धि और पांच लाख रुपये तक बीमा कवरेज जैसी व्यवस्थाओं ने उद्यमियों को जोखिम प्रबंधन में सहूलियत प्रदान करने का काम किया है। इन उपायों से निवेश वातावरण मजबूत हुआ है।

बढ़ रहा है रोजगार और आर्थिक प्रभाव

प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों का असर रोजगार सृजन पर भी पड़ा है। एमएसएमई क्षेत्र पहले से ही करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार रहा है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से इसमें नए अवसर जुड़े हैं। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सप्लाई चेन से जुड़ने के कारण ग्रामीण और अर्धशहरी इकाइयों को व्यापक बाजार हासिल हुआ है।